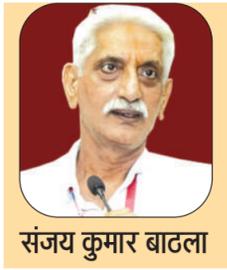


● 03 शिवजी के अनन्य भक्त: भूमी और उनके तीन पैरों का रहस्य एक अद्भुत कथा! ● 06 भारतीय ज्ञान परंपरा और विज्ञान शिक्षा: सोच-समझकर आगे बढ़ने की आवश्यकता ● 08 कांग्रेस ने पूर्व मंत्री एवं उनके पत्नी की गिरफ्तारी पर पुलिस की आलोचना की

## दिल्ली परिवहन आयुक्त की चाणक्य नीति: ई-रिक्शा पंजीकरण अपने आप बंद



संजय कुमार बाटला

दिल्ली की सड़कों पर सार्वजनिक परिवहन की बढ़ती जगजाहिर है। जनता गंतव्य से गंतव्य तक सुरक्षित, समयबद्ध सेवा के अभाव में निजी वाहनों पर निर्भर हो रही है, जिससे जाम, दुर्घटनाएँ और प्रदूषण बढ़ रहा है।

ई-रिक्शा पंजीकरण पर अनौपचारिक रोक ने अवैध वाहनों की संख्या और बढ़ाने का खतरा पैदा कर दिया है।

सार्वजनिक परिवहन का संकट दिल्ली, राष्ट्र की राजधानी होने के बावजूद, सार्वजनिक सवारी सेवा में शून्यता का शिकार है।

सड़कों पर अवैध वाहनों का बोलबाला है, जो निजीकरण, ट्रैफिक जाम, दुर्घटनाओं और वायु प्रदूषण का मुख्य कारण बने हुए हैं।

जनता का समय और धन बर्बाद हो रहा है, जबकि ई-रिक्शा जैसे पर्यावरण-अनुकूल विकल्प व्यवस्था के अभाव में अवैध हो रहे हैं।

पंजीकरण प्रक्रिया में अनियमितताएँ परिवहन विभाग की



शाखाओं ने चालक लाइसेंस के बिना ई-रिक्शा पंजीकृत किए, जबकि यह अनिवार्य दस्तावेज है।

विजिलेंस शाखा ने शिकायत पर जांच शुरू की और सभी पंजीकृत फाइलें मंगवाईं, जिसके बाद बिना किसी औपचारिक आदेश के पंजीकरण ठप हो गया।

एक ही लाइसेंस पर कई ई-रिक्शा पंजीकृत पाए गए, जो एसओपी का स्पष्ट उल्लंघन है।

लाइसेंस प्राप्ति के अवरोध ई-रिक्शा चालक लाइसेंस के लिए दिल्ली पुलिस का सीबीसी (चरित्र प्रमाण पत्र) अनिवार्य है, जो ऑनलाइन सेवा कई महीनों से बंद पड़ी है। डीटीसी (चालक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र) के लिए मान्यता प्राप्त निर्माताओं को अपलोड पोर्टल

परिवहन विभाग स्वयं व्यावसायिक सार्वजनिक सवारी सेवा के लिए उपलब्ध ई-वाहनों के पंजीकरण रोक रहा है, फिर प्रदूषण-मुक्त दिल्ली का दावा कैसे?

अवैध ई-रिक्शा बढ़ने से सड़क सुरक्षा, यातायात और पर्यावरण खतरे में है। सरकार को तत्काल पोर्टल सक्रिय कर प्रक्रिया सुगम बनानी चाहिए।

**जनहित में मांग:**  
दिल्ली पुलिस सीबीसी सेवा तत्काल बहाल करे, परिवहन विभाग डीटीसी अपलोड करने का पोर्टल वाहन पर तत्काल चालू करे।

**मुख्य बिंदु**

1. चालक चरित्र प्रमाण पत्र और परिवहन विभाग के वाहन पोर्टल पर चालक प्रशिक्षण प्रमाणपत्र अपलोड ना होने के कारण ई-रिक्शा पंजीकरण बंद
2. रोजगार के नाम पर हजारों चालकों द्वारा अवैध संचालन,
3. पंजीकरण प्रक्रिया ठप होने से नए ई-रिक्शा उपलब्ध नहीं और अवैध वाहनों की गिनती में बढ़ोतरी,
4. सीबीसी/डीटीसी सेवाओं के अभाव में लाइसेंस संभव नहीं।
5. ट्रैफिक पुलिस ने 15,000+ बिना पंजीकरण वाले ई-रिक्शा जब्त किए, कारण स्वयं दिल्ली परिवहन विभाग और दिल्ली पुलिस,
6. नाबालिग चालक और बिना व्यावसायिक लाइसेंस, हादसे व जाम बढ़े। जिम्मेदार कौन ?

## मादीपुर विधानसभा में कूड़ा घर का विरोध: जनता का सशक्त संघर्ष

मादीपुर विधानसभा में कूड़ा घर का विरोध: जनता का सशक्त संघर्ष - शहीद भगत सिंह कालोनी में नया कूड़ा घर बनाने की कोशिश पर भारी विरोध, एमसीडी कर्मचारी लौटे



संजय कुमार बाटला

पश्चिमी दिल्ली के मादीपुर विधानसभा के वार्ड 92 में शहीद भगत सिंह कालोनी में कूड़ा घर को लेकर स्थानीय निवासियों का आक्रोश आज भड़क उठा।

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के पश्चिमी क्षेत्र के अधिकारियों द्वारा आवासन दिए जाने के बावजूद पुराना कूड़ा घर हटाया नहीं गया और अब उसी स्थान पर नया पक्का कूड़ा घर जिसमें कूड़े से खाद बनाने वाली मशीन लगाने की योजना है, बनाने का टेंडर पास कर दिया।

**रिहायशी क्षेत्र में कूड़े से खाद बनाने की योजना** किसी भी नियम, कानून के तहत दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम रिहायशी क्षेत्र में खुला कूड़ा घर तक नहीं बना सकती और मादीपुर विधानसभा क्षेत्र वार्ड 92 शहीद भगत सिंह कालोनी में मुख्य सड़क पर कूड़े से खाद बनाने का टेंडर पास करना सीधे सीधे निगम पार्षद, निगम अधिकारियों पर गैर कानूनी कार्रवाई में लिप्त होने के संकेत देते हैं।

आपकी जानकारी के लिए याद करवा दे की इस वार्ड की निगम पार्षद और उनके

पति के खिलाफ पहले भी कई बाते उठ चुकी हैं और उनका बोलना की अगले चुनाव में यह वार्ड उनके क्षेत्र में नहीं आता तो यहां कोई विकास का कार्य क्यों करवाए, जो यह सिद्ध करता है की इस टेंडर के पीछे वह और नगर निगम के आला अधिकारी पश्चिम क्षेत्र मिलकर खेल रहे हैं।

आज जब उस स्थान पर निरीक्षण करने के लिए ठेकेदार और दिल्ली नगर निगम का छोटे स्तर का अधिकारी पहुंचे तो कालोनीवासियों का गुस्सा फूट पड़ा और जोरदार विरोध प्रदर्शन किया।

**आवासन का उल्लंघन:** एमसीडी अधिकारियों ने कालोनीवासियों को कूड़ा घर हटाने का वादा किया था, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई।

**नया टेंडर और निरीक्षण:** कूड़े से खाद बनाने वाली मशीन के लिए टेंडर पास, ठेकेदार व कर्मचारियों का निरीक्षण शुरू। जन विरोध का स्वरूप: सर्व धर्म मित्र मंडल के अध्यक्ष के.के. छावड़ा के नेतृत्व में भारी भीड़ ने विरोध किया; बटवू व अस्सुविधा का हवाला देकर नया कूड़ा घर बनाने से इनकार।

**प्रमुख उपस्थित:** रीतू वर्मा

(एडवोकेट), सचिन वर्मा, वेद वर्मा, मनोहर सिंह, राबेल सिंह, बलवीर सिंह, प्रीतपाल सिंह, कुलदीप सिंह, जसवंत बजाज।

**परिणाम:** विरोध के दबाव में एमसीडी कर्मचारी व ठेकेदार वापस लौट गए।

यह घटना न केवल स्थानीय स्तर पर एमसीडी की लापरवाही को उजागर करती है, बल्कि दिल्ली के अन्य इलाकों में भी फैल रही कूड़ा समस्या का प्रतीक है।

पुराने कूड़ा घर से पहले ही कालोनीवासी बटवू व स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं, ऐसे में नया निर्माण असहनीय है। प्रशासन को तत्काल हस्तक्षेप कर वादा निभाना चाहिए, वरना जन आंदोलन और तेज होगा।

जनहित में दिल्ली सरकार, विधायक क्षेत्र, एमसीडी पार्षदों व अधिकारियों से मांग है कि कूड़ा घर हटाने की प्रक्रिया तेज करें और वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करें।

**स्वच्छ दिल्ली का सपना तभी साकार होगा जब नागरिकों की आवाज सुनी जाएगी।**

## दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का संदेश: "रोड सेफ्टी सबकी जिम्मेदारी है - नियमों का पालन करें, जान बचाएं।"

स्वतंत्र सिंह भुल्लर नई दिल्ली

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस वीक (16-22 फरवरी 2026) के मौके पर, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने पूरे देश में कम्प्यूटरी की भागीदारी, रोड सेफ्टी अवेयरनेस और पब्लिक वेलफेयर पर फोकस करते हुए कई असाधारण प्रोग्राम किए। हफ्ते भर चलने वाली इन कोशिशों ने डिपार्टमेंट के एक सुरक्षित और डिजिटल ट्रैफिक सिस्टम को बढ़ावा देने, रोड सेफ्टी के बारे में अवेयरनेस फैलाने और लोगों के साथ कम्प्यूटेशन को मजबूत करने के लगातार कमिटमेंट को हाईलाइट किया। एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस (ट्रैफिक) सत्यवीर कटारा के गाइडेंस और सुपरविजन में, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सुरक्षित सड़क बनाने और जिम्मेदार ट्रैफिक बिहेवियर को बढ़ावा देने के अपने इरादे को फिर से पक्का किया।

पुलिस परिवारों को भलाई के हिस्से के तौर पर, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल मालवीय नगर में एक खास प्रोग्राम हुआ, जहां दिल्ली पुलिस के जवानों के परिवार वालों को इमरजेंसी हेल्थ सिचुएशन के लिए जान बचाने वाले स्क्रिप्ट सिखाने के लिए CPR (कार्डियो-पल्मोनरी



रिसिस्टेंशन) ट्रेनिंग दी गई। इसके साथ ही, रोड सेफ्टी पर एक दिलचस्प स्ट्रीट प्ले पेश किया गया, जिसमें ट्रैफिक नियमों का पालन करने, सड़क पर सुरक्षित व्यवहार और जिम्मेदार नागरिक होने के संदेश मजबूत तरीके से दिए गए। 135 से ज्यादा परिवार के सदस्यों और बच्चों ने जोश के साथ हिस्सा लिया, जिससे यह इवेंट जानकारी भरा और यादगार बन गया।

भविष्य के जिम्मेदार नागरिक तैयार करने के लिए, स्कूलों में खास जागरूकता अभियान भी चलाए गए। MCD प्राइमरी स्कूल दयालपुर और

लवली विस्टा स्कूल निर्माण विहार में हुए प्रोग्राम में लगभग 273 स्टूडेंट्स और 14 टीचरों ने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। इंटरैक्टिव सेशन में ट्रैफिक साइन और सिग्नल, पैदल चलने वालों की सुरक्षा, हेलमेट और सीट बेल्ट का महत्व और सुरक्षित सड़क पर चलने के तरीकों पर डेमो स्ट्रेशन शामिल थे। एक रोड सेफ्टी क्विज कॉम्पिटिशन भी आयोजित किया गया, जिसमें स्टूडेंट्स ने उत्साह से हिस्सा लिया, सवाल पूछे और जिम्मेदार ट्रैफिक व्यवहार पर अपने विचार शेयर किए।

लोगों तक पहुंच को मजबूत करने के

लिए, राजा हरिश्चंद्र चौक नरैला, द्वारका सेक्टर-1 रेड लाइट, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल मालवीय नगर और लाडो सराय जैसे बड़े ट्रैफिक चौराहों पर जमीनी जागरूकता अभियान चलाए गए। इन कैम्पेन के दौरान, ट्रैफिक अधिकारियों ने 13,300 से ज्यादा सड़क इन्स्टाल करने वालों से सीधे बात की, जिनमें पैदल चलने वाले, साइकिल चलाने वाले, टोपिया वाहन चलाने वाले और ड्राइवर शामिल थे। ट्रैफिक सिग्नल मानने, लेन डिस्टिंक्शन, हेलमेट और सीट बेल्ट का जरूरी इन्स्टाल, गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इन्स्टाल न करने और सड़क पर शिफ्टाचार के महत्व को बताने वाले पैम्फलेट बांटे गए। इन कोशिशों से लोगों में जागरूकता काफी बढ़ी और जिम्मेदारी से गाड़ी चलाने को बढ़ावा मिला।

दिल्ली पुलिस वीक 2026 के तहत इन कोशिशों के जरिए, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों की भलाई और जागरूकता के लिए अपना कमिटमेंट दिखाया। लगातार कोशिशों से, डिपार्टमेंट सभी नागरिकों के लिए सुरक्षित सड़कें, बेहतर ट्रैफिक डिस्टिंक्शन और सुरक्षित और नियमों का पालन करने वाला ट्रैफिक माहौल पक्का करने के लिए डेडिकेटेड है।

टेंपल आफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर अलाइड ट्रस्ट पंजीकृत <https://tolwa.com/about.html> | [tolwaindia@gmail.com](mailto:tolwaindia@gmail.com), [tolwadelhi@gmail.com](mailto:tolwadelhi@gmail.com)



पिकी कुडू

सिर्फ 02 मिनट दीजिए। जिन हजारों लोगों ने इस बात को समझा है, वे कभी साइबर धोखाधड़ी में फंसे ही नहीं। ये 02 मिनट आपको घंटों की परेशानी से बचाएँ और आपकी डिजिटल जिंदगी को सुगम बनाएँ।

SMS को कमजोरी पहचानें - SMS कोड दूरसंचार नेटवर्क से होकर गुजरते हैं, जिन्हें बीच में रोका जा सकता है। - SIM-swap धोखाधड़ी, फिशिंग और मैलवेयर SMS को

## आज का साइबर सुरक्षा विचार: SMS से हटकर Authenticator या Passkey अपनाइए - खुद को साइबर धोखाधड़ी से पूरी तरह सुरक्षित बनाइए।

बेहद असुरक्षित बनाते हैं। - हैकर SMS डिलीवरी में देरी और रोडब्लॉक का फायदा उठाते हैं।

1. Authenticator ऐप अपनाएँ - भरोसेमंद ऐप जैसे Google Authenticator, Microsoft Authenticator, या Authy इंस्टॉल करें। - ये आपके डिवाइस पर TOTP (Time-based One-Time Passwords) लोकली जनरेट करते हैं। - कोड हर 30 सेकंड में बदलते हैं, ऑफलाइन भी काम करते हैं और कभी असुरक्षित नेटवर्क से होकर नहीं गुजरते। - अपने बैंकिंग, ईमेल और

सोशल मीडिया अकाउंट्स को इन ऐप्स से लिंक करें और तुरंत सुरक्षा पाएँ।

2. पासकी (Passkey) अपनाएँ - पासवर्ड रहित सुरक्षा - पासकी एक डिजिटल क्रेडेंशियल है जो आपके फोन या कंप्यूटर में सुरक्षित रहता है। - लॉगिन करते समय आपका डिवाइस प्राइवेट की से एक चैलेंज साइन करता है। - सर्वर इसे पब्लिक की से वेरिफाई करता है - न पासवर्ड, न



SMS, न इंटरसेप्शन। - हैकर आपका यूजरनेम जान भी ले तो वे बायोमेट्रिक या डिवाइस-लेवल सुरक्षा को पार नहीं कर सकते।

पासकी सेटअप के छोटे कदम

- चरण 1: अकाउंट की Security / Sign-in Settings खोलें।
- चरण 2: Add Passkey या Create Passkey चुनें।
- चरण 3: डिवाइस आपसे PIN, फिंगरप्रिंट या फेस ID से पुष्टि करेगा।
- चरण 4: अगली बार लॉगिन पर पासकी अपने-आप काम करेगी।

डिवाइस है।

4. सांस्कृतिक बदलाव लाएँ - महत्वपूर्ण खातों के लिए SMS पर निर्भर रहना बंद करें। - सहकर्मियों, परिवार और नागरिकों को Authenticator ऐप या Passkeys अपनाने के लिए प्रेरित करें। - संस्थानों को SOPs और जागरूकता अभियानों को इस बदलाव के अनुरूप अपडेट करना चाहिए।

**मुख्य संदेश**  
\* SMS पुराना हो चुका है। Authenticator ऐप और Passkeys ही भविष्य हैं।  
\* SMS से दूर उठाया गया हर कदम आपको साइबर धोखाधड़ी से पूरी तरह सुरक्षित बनाता है।

# स्वास्थ्य विशेष

स्वास्थ्य आपका कोशिश हमारी

## झुर्रियां रोकना चाहते हैं वह भी बिना खर्च के



पिंकी कुंडू

से विपरीत तत्व निकालकर त्वचा को स्वच्छ और चमकदार बनाने में सहायक माना जाता है!

**वैज्ञानिक कारण:** - रिसर्च बताती है कि विटामिन - सी एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो कोलेजन सिंथेसिस सपोर्ट करता है। विटामिन - ई, फ्री - रेडिकल डैमेज से बचाता है, और विटामिन - ए स्किन रिन्यूअल में मदद करता है!

**फायदे:**  
\* झुर्रियां धीमी पड़ती हैं  
\* डेड स्किन रिमूव  
\* नेचुरल ग्लो  
\* स्किन स्मूद और साफ  
**नुकसान:**  
\* बहुत ज्यादा सेवन से संवेदनशील लोगों में दिक्कत  
\* कच्चा पपीता प्रेग्नेंसी में न लें  
\* एलर्जी हो तो पहले पैच टेस्ट



## जोश और ताकत के लिए अमरूद

पिंकी कुंडू

**अ**गर शरीर में सुस्ती, जल्दी थकान या जोश की कमी महसूस होती है, तो रोज 1 कटोरी ताजा अमरूद खाना ऊर्जा और सहनशक्ति सपोर्ट के लिए सहायक माना जाता है।

अमरूद क्यों फायदेमंद माना जाता है? अमरूद में फाइबर, विटामिन सी, फोलेट, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं।

विटामिन सी, शरीर की कोशिकाओं की मरम्मत और इन्फ्लेमेशन सपोर्ट में मदद करता है, जबकि फाइबर पाचन सुधारकर पोषक तत्वों के बेहतर अवशोषण में सहायक होता है।

**संभावित फायदे**  
\* पाचन तंत्र मजबूत कर शरीर को हल्का रखना  
\* ऊर्जा स्तर और सहनशक्ति में सुधार  
\* नसों और मांसपेशियों को



पोषण

\* थकान और कमजोरी कम करने में मदद  
\* समग्र शारीरिक ताकत में सकारात्मक असर  
**कैसे और कब लें?**  
\* सुबह या दोपहर 1 कटोरी कटा हुआ अमरूद लें  
\* चाहें तो हल्का काला नमक मिलाकर खा सकते हैं

\* 3-4 हफ्ते नियमित सेवन करें **जरूरी सावधानी**  
\* ज्यादा मात्रा में रोज सेवन न करें  
\* गैस या पाचन समस्या हो तो कम मात्रा से शुरूआत करें  
\* डायबिटीज हो तो मात्रा नियंत्रित रखें  
\* संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद ही असली जोश और ताकत की मजबूत नींव हैं।

## “सभी आलू एक जैसे नहीं होते”



ज्यादातर लोग सोचते हैं कि आलू सिर्फ आलू होता है।  
\* वही कार्ब्स,  
\* वही अम्ल,  
\* वही दिक्कतें।

इसी सोच की वजह से कई लोगों की मेटाबोलिक हेल्थ खराब हो रही है।

मैं आपको कुछ ऐसा दिखाता हूँ जो साइंस पहले से जानता है आपके आलू का रंग उसकी ताकत के बारे में क्या कहता है

1. सफ़ेद आलू इन्हें एक सादे सफ़ेद शर्ट की तरह समझें जो काम का हो, लेकिन कुछ खास नहीं।  
\* इनमें बेसिक एंटीऑक्सीडेंट (ज्यादातर विटामिन C) होते हैं।

2. पीले आलू (यूकॉन गोल्ड) अब हम अपग्रेड कर रहे हैं। इनमें सफ़ेद आलू के मुकाबले लगभग 2 गुना ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट पावर होती है।

\* क्यों? कैरोटीनॉयड न्यूट्रिएंट्स जो आँखों को सपोर्ट करते हैं, सूजन कम करते हैं, और मेटाबोलिक बैलेंस में मदद करते हैं।

3. बैंगनी आलू यहाँ से बात सीरियस हो जाती है। बैंगनी आलू में सफ़ेद आलू के मुकाबले 20 गुना तक ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं।  
\* हॉ - बीस. गुना. ज्यादा। इनमें एंथोसायनिन भरपूर होता है, ये वही पावरफुल कंपाउंड हैं जो बेरीज में पाए जाते हैं।

\* सूजन से लड़ते हैं  
\* इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर बनाते हैं  
\* ब्लड प्रेशर और पेट की हेल्थ को सपोर्ट करते हैं

\* इस समय, बैंगनी आलू सिर्फ स्टार्च नहीं, बल्कि एक फंक्शनल फूड की तरह काम करते हैं।  
\* बहुत से लोग यह गलती करते हैं वे ब्लड शुगर की दिक्कतों, सूजन या जिद्दी वजन से जुड़े हुए भी आलू पूरी तरह से छोड़ देते हैं।

\* असली प्रॉब्लम आलू नहीं है। प्रॉब्लम क्वालिटी, रंग और तैयारी के बारे में जानकारी न होना है।  
\* आलू समझदारी से कैसे खाएं  
\* जब हो सके तो रंगीन वैरायटी

चुनें  
\* उबालें, स्टीम करें, या पकाकर टंडा करें (रेसिस्टेंट स्टार्च बोनस)  
\* प्रोटीन, सर्विज्यो और हेल्दी फ़ैट के साथ खाएं

\* ध्यान रखें कि एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा कार्ब्स को खत्म न कर दें खाना सिर्फ कैलोरी नहीं है, खाना जानकारी है और कभी - कभी, नुकसान और ठीक होने के बीच का फ़र्क - बस आपकी प्लेट का रंग होता है।

\* अगर आप इंसुलिन रेंजिस्टेंस, इन्फ्लेमेशन या वजन कंट्रोल के लिए परसनाइज्ड, एविडेंस - बेस्ड मील प्लान चाहते हैं, स्मार्ट तरीके से खाएं। ज्यादा ठीक हो।

## कैंसर से बचाव के प्रभावी उपाय (नवीनतम वैज्ञानिक जानकारी सहित)

**कैं**सर एक गंभीर लेकिन काफी हद तक रोकी जा सकने वाली बीमारी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार लगभग 30 - 50% कैंसर मामलों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाकर रोका जा सकता है। सही आहार, नशे से दूरी और सक्रिय जीवनशैली अपनाना सबसे प्रभावी बचाव है।

**इन चीजों से बचें**  
1. ठंडे पेय और अत्यधिक मीठे पेय पदार्थ  
2. पैकड/प्रोसेस्ड फलों के जूस  
3. शराब का सेवन  
4. तंबाकू, गुटखा, पान मसाला  
5. अत्यधिक प्रोसेस्ड और जंक फूड

**क्यों बचें?**  
क्योंकि इन पदार्थों में  
1. अधिक चीनी,  
2. रसायन,  
3. कृत्रिम रंग/फ्लेवर और  
4. हानिकारक तत्व होते हैं जो शरीर में सूजन (inflammation), मोटापा और कोशिकाओं की असामान्य वृद्धि को बढ़ावा देते हैं — जो कैंसर का प्रमुख कारण बन सकते हैं।

**इन स्वस्थ विकल्पों को अपनाएं**  
1. पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ और शुद्ध पानी  
2. ताजे फल और बिना चीनी के प्राकृतिक जूस



3. घर का बना संतुलित और पौष्टिक भोजन  
4. अधिक मात्रा में फल, सब्जियाँ, साबुत अनाज और फाइबरयुक्त आहार

5. नियमित शारीरिक गतिविधि (कम से कम 30 मिनट प्रतिदिन)  
क्यों आवश्यक है? प्राकृतिक और संतुलित भोजन शरीर की प्रतिरोधक क्षमता (Immunity) बढ़ाता है, वजन नियंत्रित रखता है और कोशिकाओं को स्वस्थ बनाए रखता है।

**अव्याय्यकर आदतों से जुड़े प्रमुख कैंसर**  
1. कोलोरेक्टल कैंसर अत्यधिक प्रोसेस्ड मीट, कम फाइबर वाला आहार, कोल्ड ड्रिंक्स और मोटापा इसका जोखिम बढ़ाते हैं।  
\* नवीनतम शोध: उच्च फाइबर और साबुत अनाज का सेवन जोखिम कम करता है।

2. इसोफेजियल कैंसर शराब, कोल्ड ड्रिंक्स और तंबाकू इसका प्रमुख कारण हैं। गर्म पेय का अत्यधिक सेवन भी जोखिम बढ़ा सकता है।

3. पेट (गैस्ट्रिक) कैंसर अत्यधिक नमकीन, प्रोसेस्ड भोजन, कोल्ड ड्रिंक्स और धूम्रपान से जोखिम बढ़ता है। ताजे फल - सब्जियाँ सुरक्षा प्रदान करती हैं।

4. लिंफ कैंसर शराब और कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन, मोटापा और हेपेटाइटिस संक्रमण प्रमुख कारण हैं। हेपेटाइटिस-B का टीकाकरण सुरक्षा देता है।  
5. अन्यायशय (पैक्रियाटिक) कैंसर धूम्रपान, कोल्ड ड्रिंक्स, मोटापा और मधुमेह इसके जोखिम कारक हैं।  
**\* नवीनतम वैज्ञानिक सुझाव (2024-2025 अपडेट)**  
\* शराब, धूम्रपान, तंबाकू, गुटखा, पान मसाला और कोल्ड

ड्रिंक्स पूरी तरह छोड़ना कैंसर जोखिम कम करने का सबसे प्रभावी तरीका है।  
\* नियमित व्यायाम (150 मिनट प्रति सप्ताह) कैंसर और मोटापे दोनों को नियंत्रित करता है।  
\* वीएमआई संतुलित रखना आवश्यक है।  
\* एचपीवी और हेपेटाइटिस - बी वैक्सीन कुछ कैंसर से सुरक्षा प्रदान करते हैं।  
\* 40 वर्ष के बाद नियमित स्वास्थ जांच (स्क्रीनिंग) करना लाभकारी है।  
\* प्लॉट-बेस्ड आहार को वैश्विक स्वास्थ्य एजेंसियाँ प्राथमिकता दे रही हैं।

**निष्कर्ष** हालाँकि कोई भी उपाय 100% कैंसर से सुरक्षा की गारंटी नहीं देता, लेकिन स्वस्थ भोजन + नशामुक्त जीवन + नियमित व्यायाम + समय पर जांच = कैंसर जोखिम में महत्वपूर्ण कमी।

## मल में दिखने वाले बदलाव होने वाली कई बीमारियों के संकेत, जाने

पिंकी कुंडू

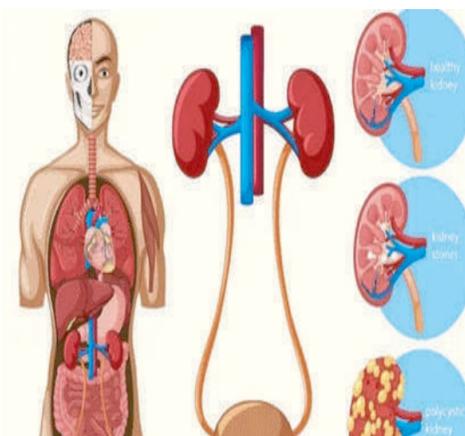
**ह**मारे शरीर के अंदर होने वाली बीमारियों का पता अक्सर शरीर हमें पहले ही देने लगता है लेकिन ज्यादातर लोग इनकी पहचान करने में असमर्थ होते हैं।

बहुत कम लोगों को इनकी जानकारी है, कि हमारे शरीर के अंदर होने वाली कई बीमारियाँ जिनका पता हम रोज सुबह टॉयलेट में जाकर भी लगा सकते हैं।

मल में दिखने वाले बदलाव कई बीमारियों का संकेत हो सकते हैं और खासतौर पर मल में झाग बनने के लक्षण।

\* मल में झाग अक्सर तब बनती है, जब मल में बलगम बनने लगा हो और मल में बलगम कई अंदरूनी बीमारियों का संकेत है।

इस पोस्ट में हम आपको मल में झाग बनने के कारण के पीछे की बीमारियों के बारे में बता रहे हैं।  
1. लिंवर खराब होना जब लिंवर ठीक से काम करना बंद कर देता है, तो उससे जुड़े काफी लक्षण आप सुबह मल में भी देख सकते हैं। मल में बलगम के कारण झाग बने लगना लिंवर से जुड़ी बीमारियों का एक संकेत हो सकता है, जिसे आपको गलती से भी इग्नोर नहीं करना चाहिए।  
2. शरीर में पानी की कमी:- अगर आपके शरीर में पानी की कमी हो गई है, तो इसके कारण शरीर के कई अलग-अलग हिस्सों में लक्षण देखने को मिल



सकते हैं और इनमें से एक लक्षण मल में झाग बनना भी है। अगर आपको पानी कम पीने की आदत है, तो इसके कारण मल में झाग जैसे लक्षण भी देखने को मिल सकते हैं।  
3. कब्ज:- आज के समय में कब्ज काफी सामान्य समस्या बन चुकी है और बड़ी संख्या में लोग इसी परेशान रहते हैं। कब्ज के कारण भी कुछ लोगों को मल में बलगम या झाग जैसे लक्षण देखने को मिल सकते हैं। कब्ज और मल में झाग बनना दोनों के पीछे का कारण पाचन क्रिया का ठीक से काम न करना भी हो सकता है।  
4. बवासीर:- अगर आपके मल में झाग बनने लगी है, तो आपको इसे लंबे

समय तक इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्योंकि यह बवासीर जैसी किसी बीमारी की शुरुआत का संकेत भी हो सकता है। खासतौर पर अगर आपको मल में झाग बनने के साथ-साथ खून भी महसूस हो रहा है, तो डॉक्टर से जल्द से जल्द संपर्क कर लेना चाहिए।  
5. पेट के अन्य रोग:- क्रोन डिजीज और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसी कुछ बीमारियाँ भी हैं, जिनके कारण इस तरह के लक्षण देखे जा सकते हैं। क्योंकि ऐसी बीमारियों में पेट, आंत व पाचन क्रिया गंभीर रूप से प्रभावित हो जाती है और पाचन ठीक से न होने के कारण मल में बलगम देखने को मिल सकता है।

## जिंदगी का हर पड़ाव खूबसूरत और सेहतमंद आनंद उसका अहम हिस्सा

पिंकी कुंडू

**य**ह लेख विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो संभोग (सेक्स) को सिर्फ शारीरिक क्रिया नहीं, बल्कि रिश्ते, सेहत और भावनात्मक जुड़ाव का हिस्सा मानते हैं, आनंद के साथ-साथ इसके वैज्ञानिक पहलुओं को जानना भी उतना ही जरूरी है।

**संभोग के दौरान शरीर में**  
1. ऑक्सीटोसिन (Oxytocin) और  
2. एंडोर्फिन (Endorphins) निकलते हैं, जो बेहतर नींद और रिलैक्स महसूस करने में मदद करते हैं।

\* नियमित सेक्स से तनाव हार्मोन कोर्टिसोल (Cortisol) का स्तर कम हो सकता है, जिससे मानसिक दबाव घटता है।

\* अंतरंग संबंध से डोपामिन (Dopamine) रिलीज होता है, जो खुशी और संतुष्टि का अहसास बढ़ाता है।  
\* हफ्ते में 1-2 बार यौन संबंध रखने से कुछ शोधों में पाया गया है कि इन्फ्लेमेटोरी प्रोटीन A (IgA) का स्तर बेहतर हो सकता है, जो

इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में सहायक है।  
\* नियमित और सुरक्षित संभोग से पार्टनर्स के बीच भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होता है, जिससे रिश्ते में विश्वास बढ़ता है।  
\* सेक्स एक हल्की शारीरिक कसरत की तरह काम करता है —

\* दिल की धड़कन बढ़ती है और रक्त संचार बेहतर होता है।  
\* औसतन 4 - 6 कैलोरी प्रति मिनट तक बर्न हो सकती हैं, जो शरीर को एक्टिव रखती हैं।

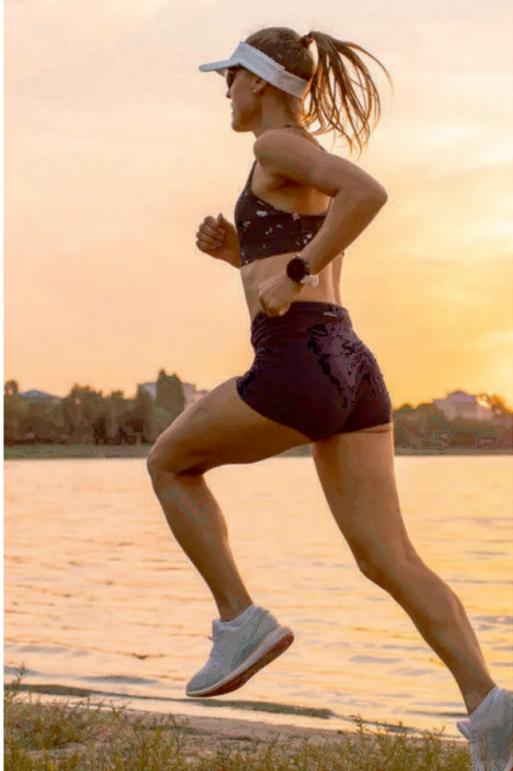
\* ऑर्गज्म के दौरान एंडोर्फिन रिलीज होने से कुछ लोगों में सिरदर्द या हल्के दर्द में राहत महसूस होती है।  
\* नियमित अंतरंगता से ब्लड प्रेशर संतुलित रखने में मदद मिल सकती है (हालाँकि यह व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है)।

\* पुरुषों में नियमित स्खलन से प्रोस्टेट स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव की बात कुछ अध्ययनों में की गई है।  
\* सेक्स के दौरान बनने वाले हार्मोन त्वचा में रक्त

प्रवाह बढ़ाते हैं, जिससे चेहरे पर प्राकृतिक चमक आ सकती है।  
\* सुबह के समय टेस्टोस्टेरोन का स्तर सामान्यतः अधिक होता है, जो पुरुषों में शुक्राणु की गुणवत्ता और ऊर्जा पर सकारात्मक असर डाल सकता है।

\* संतुलित और सहमति से किया गया सेक्स आत्मविश्वास और स्टेमिना दोनों को बेहतर कर सकता है। सबसे जरूरी बात — सुरक्षित सेक्स (कंडोम की उपयोग, एसटीआई की जानकारी, और सहमति) से शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य दोनों सुरक्षित रहते हैं।

अगर आप अपनी जिंदगी का आनंद नहीं ले रहे हैं, तो याद रखिए — सेक्स कोई शर्म की बात नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक और वैज्ञानिक प्रक्रिया है। सही जानकारी, आपसी सहमति और सम्मान के साथ इसे अपनाना ही समझदारी है।  
जिंदगी का हर पड़ाव खूबसूरत है और सेहतमंद आनंद उसका अहम हिस्सा हो सकता है, बाकी आप खुद समझदार हैं।





# समाधान शिविर से आमजन की समस्याओं का हो रहा त्वरित निपटान: डीडीपीओ

परिवहन विशेष न्यूज

– जिला स्तरीय समाधान शिविर में डीडीपीओ निशा तंवर ने सुनी शिकायतें, संबंधित विभागों को दिए निर्देश

झज्जर, 19 फरवरी। जिला प्रशासन द्वारा नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उपयुक्त स्वामित्व रविन्द्र पाटिल के मार्गदर्शन में समाधान शिविरों का आयोजन लगातार किया जा रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को लघु सचिवालय में जिला स्तरीय समाधान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें डीडीपीओ निशा तंवर ने नागरिकों को शिकायतें सुनीं और संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

शिविर में भूमि संबंधी, पेंशन, पारिवारिक पहचान पत्र, अतिक्रमण, पानी व बिजली से जुड़ी नौ समस्याएं प्रमुख रूप से सामने आईं। डीडीपीओ ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतों का समाधान प्राथमिकता के



आधार पर करते हुए पारदर्शिता और संवेदनशीलता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि समाधान शिविर आमजन और प्रशासन के बीच संवाद को मजबूत करने का प्रभावी माध्यम है। इन शिविरों के माध्यम से लोगों को एक ही

स्थान पर विभिन्न विभागों की सेवाएं उपलब्ध होती हैं तथा समस्याओं का शीघ्र समाधान संभव हो पाता है, जिससे प्रशासन के प्रति विश्वास और अधिक सुदृढ़ होता है। इस अवसर पर एसीपी प्रदीप नैन,

बिजली विभाग के कार्यकारी अभियन्ता प्रदीप कुमार, नायब तहसीलदार, मनीष बंसल सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। उपमंडल स्तर पर समाधान शिविर उपमंडल बहादुरगढ़ में एसडीएम

अभिनव सिंघाव, बेरी में एसडीएम रेणुका नांदल तथा बादली में एसडीएम डॉ रमन गुप्ता की अध्यक्षता में उपमंडल स्तरीय समाधान शिविर आयोजित किए गए, जिनमें लोगों की समस्याएं सुनते हुए आवश्यक कार्रवाई की गई।

## संशोधित स्टेज कैरिज स्कीम के तहत झज्जर जिले में विभिन्न मार्गों पर परमिट हेतु आवेदन आमंत्रित

परिवहन विशेष न्यूज

–जिला परिवहन अधिकारी एवं प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण झज्जर के सचिव अंकित कुमार चौकसे ने दी जानकारी

बहादुरगढ़ (झज्जर), 19 फरवरी। जिला परिवहन अधिकारी एवं प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण झज्जर के सचिव अंकित कुमार चौकसे ने बताया कि संशोधित स्टेज कैरिज स्कीम के तहत झज्जर जिले में विभिन्न अधिसूचित मार्गों पर स्टेज कैरिज परमिट प्रदान करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक व्यक्ति 18 फरवरी से आगामी 15 दिनों के अंदर-अंदर आवेदन कर सकते हैं।

प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण के सचिव अंकित कुमार चौकसे आईएसएस ने झज्जर जिले के अधिसूचित मार्गों की जानकारी देते हुए बताया कि टिकरी बॉर्डर से रोहतक वाया बहादुरगढ़, सांपला, झज्जर से चरखी दादरी वाया तलाव, गवालिसन, छुछकवास, इमलोटा, मोरवाला, समसपुर, झज्जर से कोसली वाया जहाजगढ़, छुछकवास, मातनहेल, लडायन, साल्हावास, झज्जर से खरखोटा वाया छारा, सांपला, हसनगढ़, बहादुरगढ़ से बहुशौलरी वाया दुल्हेड़ा, झज्जर, जहाजगढ़, छुछकवास, मातनहेल, सासरीली, झाड़ली प्लांट, झज्जर से गुरुग्राम वाया दादरी तोय, फरुखनगर, बेरी से फरुखनगर वाया झज्जर, दादरी तोय, झज्जर से कनीना

वाया गवालिसन, छुछकवास, निवादा, साल्हावास, कोसली, झज्जर से ढांसा बॉर्डर वाया बादली, गांव सिवाना से ढांसा बॉर्डर वाया बेरी, झज्जर, बादली, झज्जर से रोहतक वाया बहराना, दिमाना, चुलाना, खरड़, कारो, शिमली, झज्जर से रेवाड़ी वाया सिलाना, सिलाना, कुलाना, बेरी से बहादुरगढ़ वाया दुजाना चौक, छारा, मातन, झज्जर से बहादुरगढ़ वाया कबलाना, दुल्हेड़ा, माजरा, गांव शेरिया से बहादुरगढ़ वाया मदाना, दुजाना, छारा, मांडोटी, झज्जर से दादरी वाया ढांसा बॉर्डर वाया बादली, झज्जर, तलाव, रेडूवास, भूरावास, छुछकवास, झज्जर से कोसली वाया रईया, डावला, कासनी,

सुबाना, फरुखनगर से झज्जर वाया याकूबपुर, किलोई, मोड, दादरी तोय, झज्जर से कोसली वाया डावला, रईया, हसनपुर, कासनी, सुबाना, जटवाड़ा, बिठला, अम्बोली, साल्हावास, बहादुरगढ़ से झज्जर वाया माजरा, ढावड़ा, दुल्हेड़ा, कबलाना, भदानी, नेहरू कॉलेज, झज्जर से रोहतक वाया गुदा, दुजाना चौक, डीघल, करोंथा, शिमली, मायना, लडायन से झज्जर वाया कानौदा, बामरीली, बहादुरगढ़, भदानी मोड़, रासलवाला, नेहरू कॉलेज, झज्जर से दादरी वाया जहाजगढ़, छुछकवास, मातनहेल, सासरीली, बिरोहड़, सेहलंगा, गांव साल्हावास से रोहतक वाया बेरी, गांव ढाकला से गुरुग्राम वाया सुबाना, छपार,

अहरी, कुलाना, लुहारी, हेली मंडी, पटौदी, बिलासपुर चौक, बहादुरगढ़ से खरखोटा वाया कानौदा, लठारवन, सैहदपुर बहुशौलरी से रोहतक वाया झाड़ली प्लांट, छुछकवास, बेरी रूट शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इच्छुक आवेदक परिवहन आयुक्त, हरियाणा, चण्डीगढ़ कार्यालय में नॉन-रिफंडेबल शुल्क 25 हजार रुपये सहित आवेदन जमा करवाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित अवधि के पश्चात किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। विस्तृत जानकारी के लिए बहादुरगढ़ स्थित जिला परिवहन अधिकारी एवं सचिव प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

## कृषि विभाग से जुड़ी योजनाओं का लाभ उठाएं किसान : एसडीओ -खाद्य एवं पोषण सुरक्षा -पोषक अनाज के तहत जिला स्तरीय किसान जागरूकता शिविर आयोजित



परिवहन विशेष न्यूज

–पाराली प्रबंधन में उल्लेखनीय योगदान के लिए नौ किसान हुए सम्मानित

बहादुरगढ़ (झज्जर), 19 फरवरी। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा गुरुवार को उप मण्डल अधिकारी (कृषि) कार्यालय में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा - पोषक अनाज योजना के अंतर्गत जिला स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता विभाग के एसडीओ डा सुनील कौशिक ने की। शिविर में उपमंडल के आधा दर्जन से ज्यादा किसानों को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया जिन्होंने पराली प्रबंधन में उल्लेखनीय योगदान दिया है।

इस मौके पर एसडीओ डा सुनील कौशिक ने उपमंडल के सभी किसानों से एग्री स्ट्रेक किसान आईडी का पंजीकरण करवाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान युग में डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ने पर किसानों को योजनाओं का

लाभ पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से प्राप्त होगा। शिविर में विभिन्न विषय विशेषज्ञों ने किसानों को सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। कैप में कृषि विभाग के सहायक पौधा संरक्षण अधिकारी शैया राम और तकनीकी अधिकारी डा रोहित वत्स ने कृषि विभाग की विभिन्न ऑनलाइन योजनाओं से अवगत कराया। डॉ. महावीर मलिक ने मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने और पौध संरक्षण तकनीकों से किसानों को विस्तार से

अवगत कराया, वहीं विशेषज्ञ रमेश कुमार ने प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए किसानों को प्रेरित किया, जबकि कुमारी कविता ने पोषक अनाजों के महत्व पर प्रकाश डाला। इसी प्रकार बीएओ राकेश राणा ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना तथा एग्री स्ट्रेक किसान आईडी पंजीकरण प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी। पशुपालन एवं डेयरी विभाग के डॉ. रविन्द्र दहिया ने विभागीय योजनाओं की जानकारी साझा की। एडीओ रोहद प्रदीप मलिक ने मृदा नमूना एवं मृदा

स्वास्थ्य कार्ड के महत्व को समझाया। गांव माजरी के प्रगतिशील किसान जयपाल ने प्राकृतिक खेती तथा गांव छारा के संदीप ने बाजरा के मूल्यवर्धन के अनुभव साझा कर किसानों को प्रेरित किया। इस अवसर पर तकनीकी सहायक सुनील कुमार, दीपक कुमार, सांख्यिकी सहायक मुंशी राम, सुधीर कुमार, जितेन्द्र, एटीएम नवीन कुमार कृषि सुपरवाइजर जैसिका दलाल सहित विभागीय अधिकारी एवं प्रगतिशील किसान उपस्थित थे।

## बेरी में उपभोक्ता कष्ट निवारण फोरम की बैठक आज

बेरी (झज्जर), 19 फरवरी। बिजली निगम डिजीवन बेरी के उपभोक्ताओं की बिजली से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए 20 फरवरी, शुक्रवार को बिजली अदालत और उपभोक्ता कष्ट निवारण फोरम की बैठक की आयोजित की जाएगी। एसडीओ सुनील कुमार ने बताया कि बैठक उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएनएल) के बेरी कार्यालय में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित होगी। उन्होंने बताया कि बैठक में बिजली उपभोक्ताओं की बिजली बिल, कनेक्शन, लोड संबंधित समस्याओं को सुना जाएगा और उनका मौके पर ही समाधान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कोई उपभोक्ता फंसले से संतुष्ट नहीं है तो वह अपनी शिकायत अध्यक्ष अभियंता झज्जर के समक्ष रख सकता है।

## गांव पाटोदा में जिला स्तरीय किसान मेला आज, कृषि योजनाओं की मिलेगी एक ही मंच पर जानकारी

–एसडीएम अंकित कुमार चौकसे आईएसएस होंगे मुख्य अतिथि  
झज्जर, 19 फरवरी। माछरौली खंड के गांव पाटोदा में 20 फरवरी (शुक्रवार) को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के तत्वावधान में जिला स्तरीय किसान मेला का आयोजन होगा। यह मेला सुबह 11 बजे शुरू होगा, जिसमें गांव पाटोदा, लुहारी, खेड़ी सुलतान, कहाड़ी सहित आसपास के गांवों के किसान भाग लेंगे। यह जानकारी उप कृषि निदेशक डॉ जितेंद्र अहलावत ने दी। उप कृषि निदेशक ने बताया कि किसान मेले में मुख्य अतिथि के रूप में एसडीएम झज्जर अंकित कुमार चौकसे, आईएसएस शिरकत करेंगे। मेले का उद्देश्य किसानों को केंद्र व राज्य सरकार की कृषि से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी एक ही मंच पर उपलब्ध कराना है, ताकि किसान इन योजनाओं का अधिकतम लाभ उठा सकें। उन्होंने बताया कि मेले के दौरान किसानों को एग्रीस्ट्रेक (फार्मर आईडी), प्राकृतिक खेती, मेरी फसल मेरा ब्यूरो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, मेरा पानी मेरी विरासत, फसल विविधीकरण, माइक्रो सिंचाई, मृदा स्वास्थ्य कार्ड तथा फसल सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा किसानों को योजनाओं से जुड़ी प्रक्रिया, पात्रता और लाभ के बारे में विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। किसान मेले में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के साथ-साथ संबंधित अन्य विभागों द्वारा भी विभिन्न स्टॉल लगाई जाएंगी। इन स्टॉलों में किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, उन्नत बीजों, सिंचाई पद्धतियों और फसल सुरक्षा उपायों का डेमोंस्ट्रेशन करके दिखाया जाएगा, जिससे किसान व्यवहारिक रूप से इन तकनीकों को समझ सकें। डीडीए डॉ जितेंद्र अहलावत ने माछरौली खंड के किसान भाइयों से अपील की है कि वे योजनाओं में पंजीकरण और जांच के लिए अपने आवश्यक दस्तावेज साथ लेकर समय पर किसान मेले में पहुंचें। उन्होंने कहा कि इस मेले के माध्यम से किसान कृषि विभाग की योजनाओं की जानकारी लेकर अपनी खेती को अधिक लाभकारी बना सकते हैं और सरकारी सुविधाओं का पूरा फायदा उठा सकते हैं।

## गांव रायपुर में रात्रि ठहराव कार्यक्रम 20 फरवरी को : सीटीएम

– कार्यक्रम में विभागीय स्टॉल व स्वास्थ्य जांच शिविर के माध्यम से मिलेगी योजनाओं की जानकारी

झज्जर, 19 फरवरी। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की पहल पर जिला प्रशासन द्वारा प्रत्येक माह आयोजित किए जाने वाले रात्रि ठहराव कार्यक्रम का आयोजन 20 फरवरी को खंड माछरौली के गांव रायपुर स्थित राजकीय प्राथमिक पाठशाला परिसर में किया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता एडीसी जगनिसस करेंगे। एडीसी ग्रामीणों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं सुनेंगे तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों को मौके पर ही समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश देंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रशासन को गांव स्तर तक पहुंचाकर आमजन की समस्याओं का त्वरित एवं प्रभावी निवारण करना है। सीटीएम नमिता कुमारी ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए स्टॉल लगाए जाएंगे, जिससे ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में सुविधा होगी। साथ ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा, जहां नागरिकों की जांच कर आवश्यक परामर्श दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि रात्रि ठहराव कार्यक्रम प्रशासन की महत्वपूर्ण पहल है, जिसके माध्यम से अधिकारियों को गांव की जमीनी स्थिति का प्रत्यक्ष आकलन करने और विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करने का अवसर मिलता है। इससे शासन और जनता के बीच संवाद और अधिक सुदृढ़ होता है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की है कि वे इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाएं और अपनी समस्याएं, सुझाव व मांगें प्रशासन के समक्ष रखें, ताकि गांव के सर्वांगीण विकास को और गति मिल सके।

## बीपीएल महिलाओं को मिलेगा चालक व आत्मरक्षा प्रशिक्षण

– हरियाणा महिला विकास निगम ने 28 फरवरी तक मांगे आवेदन

झज्जर, 19 फरवरी। हरियाणा महिला विकास निगम, पंचकुला द्वारा बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) वर्ग की महिलाओं और लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से 21 दिवसीय चालक एवं आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। यह प्रशिक्षण बहादुरगढ़ (झज्जर) तथा रोहतक स्थित मासुति सुजुकी ट्रेनिंग सेंटर में आयोजित होगा। निगम के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि यह प्रशिक्षण केवल हरियाणा की स्थायी निवासी बीपीएल महिलाओं/लड़कियों के लिए है। पात्रता के अनुसार आवेदिका की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास निर्धारित की गई है। उच्च शैक्षणिक योग्यता रखने वाली आवेदिकाओं को वरीयता दी जाएगी।

उन्होंने बताया कि आवेदिका को दृष्टि अच्छी होनी चाहिए (रंग दृष्टिहीनता न हो) और उसके पास वैध लॉन्ग ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली या परिवार पहचान पत्र के अनुसार जिन परिवारों की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये या उससे कम है, वे भी आवेदन करने के पात्र हैं। प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को 1000 रुपये का वजीफा भी प्रदान किया जाएगा। निगम ने कैथल, झज्जर, रोहतक और जौड़ जिलों की इच्छुक एवं पात्र महिलाओं/लड़कियों से 28 फरवरी तक ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन निर्धारित प्रपत्र में सभी कॉलम सही प्रकार से भरकर तथा आवश्यक प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियां सहित ई-मेल, पंजीकृत डाक या संबंधित जिला कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से जमा करवाए जा सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र में दूरभाष नंबर, ई-मेल एड्रेस तथा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियां संलग्न करना अनिवार्य है। निर्धारित प्रपत्र संबंधित जिला प्रबंधक कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए दूरभाष नंबर 01251-299560 या ई-मेल jhajarhwcd@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है।

## श्री वैकटेश्वर कॉलेज में 'नेक्सस 2026' का भव्य शुभारंभ, सूफ़ी सुरों, युवा ऊर्जा और रचनात्मकता से गूँज उठा कैम्पस

डॉ. शंभु पवार

नई दिल्ली, 19 फरवरी। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित महाविद्यालय श्री वैकटेश्वर कॉलेज में तीन दिवसीय वार्षिक सांस्कृतिक महोत्सव 'नेक्सस 2026' का शुभारंभ 18 फरवरी को अत्यंत भव्य, अनुशासित और उल्लासपूर्ण वातावरण में हुआ। ऊर्जावान प्राचार्य प्रो. वज्रला रवि के कुशल नेतृत्व में आयोजित इस उत्सव ने कॉलेज परिसर को उल्लास, संस्कृति और युवा प्रतिभा के रंगों से सजावट कर दिया। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि द हिंदू, नई दिल्ली के रॉजिडेंट एडिटर वगीस के जॉर्ज रहे, जबकि श्री

वैकटेश्वर कॉलेज की एलुमनाई एवं प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका शिवांगिनी येशू युवराज तथा ख्यातिप्राप्त कथक नृत्यांगना प्रोमा मुखर्जी ने गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में कार्यक्रम की गरिमा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अपनी प्रेरणादायी संबोधन में प्राचार्य प्रो. वी. रवि ने कहा कि 'नेक्सस' महज एक उत्सव नहीं, बल्कि रचनात्मक सोच, सांस्कृतिक चेतना और युवा प्रतिभा का जीवंत मंच है, जो छात्रों को स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ आत्म-अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करता है। महोत्सव के पहले दिन का मुख्य

आकर्षण रही सूफ़ी नाइट, जहां अनिरुद्ध वर्मा और निजामी ब्रदर्स की भावपूर्ण प्रस्तुतियों ने समूचे परिसर को सूफ़ियाना रंग में रंग दिया। इस अवसर पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के. मोहन नायडू मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान कॉलेज परिसर छात्रों की भारी भीड़ से खचाखच भरा रहा और प्रत्येक प्रतियोगिता में युवाओं का उत्साह देखते ही बनता था। आयोजन को सफल बनाने में कॉलेज स्टूडेंट्स यूनिफन की भूमिका उल्लेखनीय रही। आयोजकों के अनुसार, उत्सव के दूसरे दिन 'डीजे मदारी नाइट' जबकि समापन दिवस पर प्रसिद्ध पार्श्वगायक

अंकित तिवारी की लाइव प्रस्तुति महोत्सव का शिखर आकर्षण होगी, जिसका छात्रों को बेसब्री से इंतजार है। 'नेक्सस 2026' ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया है कि श्री वैकटेश्वर कॉलेज न केवल शैक्षणिक उत्कृष्टता का केंद्र है, बल्कि सांस्कृतिक चेतना और युवा सृजनात्मकता का भी सशक्त मंच है। समारोह में उप-प्राचार्य प्रो. नंदिता नारायणासामी, कोषाध्यक्ष डॉ. कृष्ण कुमार, प्रशासनिक अधिकारी पवन कुमार पाण्डेय, फाइन आर्ट्स एंसेम्बलेशन के संयोजक डॉ. एम. कृष्णा राव तथा स्टूडेंट्स स्टाफ एडवाइजर प्रो. ओम प्रकाश की गरिमामयी उपस्थिति रही।



# ‘जय शिवाजी, जय भारत’ के जयघोष से गुंजा सातारा, 12 हजार युवाओं ने भव्य मशाल यात्रा में लिया विकसित भारत का संकल्प



संगिनी घोष

छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत को समर्पित ऐतिहासिक आयोजन महान मराठा शासक की जयंती पर हजारों युवाओं की मौजूदगी ने समारोह को असाधारण उत्साह और ऊर्जा से भर दिया। कार्यक्रम ने बीरता, सुरासन और सांस्कृतिक गौरव के प्रतीक शिवाजी महाराज की प्रेरणादायक विरासत को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया।

**MY Bharat की मशाल पदयात्रा बना मुख्य आकर्षण**  
समारोह का सबसे प्रमुख आकर्षण

प्रतीकात्मक पदयात्रा रही, जिसमें लगभग 12,000 युवाओं ने मशाल लेकर “जय शिवाजी, जय भारत” के नारे लगाए। यह यात्रा एकता, संकल्प और राष्ट्र निर्माण में युवाओं की सक्रिय भागीदारी की भावना का प्रतीक बनी।

ऐसे देखें तो, यह आयोजन केवल एक स्मरणोत्सव नहीं बल्कि विकसित और सशक्त भारत के संकल्प का सामूहिक प्रदर्शन भी था।

**देशभक्ति और युवा ऊर्जा से भर माहौल**

कार्यक्रम में तिरंगे और भगवा ध्वजों की मौजूदगी, सामूहिक नारों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने वातावरण को राष्ट्रभक्ति से सराबोर कर दिया। आयोजकों का कहना था कि ऐसे आयोजन युवाओं को इतिहास से जोड़ते हैं और उन्हें आधुनिक समय में प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने का संदेश देते हैं।

**नेतृत्व और राष्ट्रनिर्माण का संदेश**  
वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि शिवाजी महाराज के स्वराज, प्रशासनिक कुशलता और जनकल्याण के सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं। युवाओं को नवाचार, सामाजिक सेवा और नागरिक जिम्मेदारी



जैसे क्षेत्रों में योगदान देने के लिए प्रेरित किया गया।

**मुख्य बिंदु**

\* शिवाजी जयंती समारोह में करीब 12 हजार युवाओं की भागीदारी।  
\* मशाल यात्रा ने एकता और संकल्प का प्रतीक प्रस्तुत किया।  
\* पूरे कार्यक्रम में गुंजे देशभक्ति के नारे।

\* राष्ट्रनिर्माण में युवा भागीदारी पर जोर।  
\* शिवाजी महाराज के नेतृत्व और सुरासन के आदर्शों को रेखांकित किया गया।

\* आयोजन ने इतिहास और आधुनिक विकास दृष्टि को जोड़ा।

**आगे की दिशा**  
Press Information Bureau से

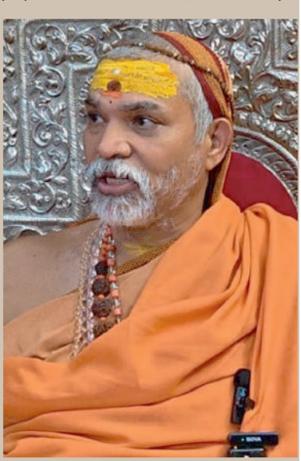
जुड़े अधिकारियों के अनुसार, इसी तरह के युवा-केंद्रित कार्यक्रम अन्य क्षेत्रों में भी आयोजित किए जा सकते हैं ताकि युवाओं में नागरिक जागरूकता और राष्ट्रीय भागीदारी को बढ़ावा मिले। विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसे आयोजन ऐतिहासिक प्रेरणा को वर्तमान आकांक्षाओं से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

## 21वें दिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने तीखा हमला किया; 11 मार्च को “लखनऊ चलो” का आह्वान किया

वाराणसी: वाराणसी के केदारघाट स्थित श्री विद्यामठ में उत्तरप्रदेशीय ज्योतिष पीठ के जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिए गए 40 दिन के अल्टीमेटम के 20 दिन बाद कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आरोप लगाया कि इस दौरान मुख्यमंत्री के “हिंदू” के तौर पर काम करने के कोई संकेत नहीं दिखे और गोरक्षा के मुद्दे पर एक रहस्यमयी चुप्पी थी।

शंकराचार्य ने कहा कि सरकार ने फिल्म “गोदान” को टैक्स-फ्री करने जैसे सांकेतिक कदम उठाए, लेकिन गाय को “राज्य माता” घोषित करने और बीफ एक्सपोर्ट पर पूरी तरह बैन लगाने जैसे मुख्य मांगों पर चुप रही। 20वीं पशुधन जनगणना के डेटा का हवाला देते हुए उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में मवेशियों की आबादी बढ़ी, जबकि उत्तर प्रदेश में घटी। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि “ईज ऑफ ड्रूंग बिजनेस” की आड़ में, उत्तर प्रदेश देश के बड़े मीट एक्सपोर्ट करने वाले राज्यों में से एक बन गया है, जो उनके अनुसार गोरक्षा के दावों के उलट है। उन्होंने संत समुदाय और आखाड़ों से भी इस मुद्दे पर साफ स्टैंड लेने की अपील की।

आंदोलन को एक नई दिशा देते हुए, शंकराचार्य ने 11 मार्च, 2026 को “लखनऊ चलो” का ऐलान किया और कहा कि जब तक “गोमाता” के अधिकार सुरक्षित नहीं हो जाते, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।



## आगरा में शिवाजी जयंती पर निकली भव्य रैली, कार्यकर्ताओं ने लिया संकल्प

परिवहन विशेष न्यूज

आगरा, संजय सिंह। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ भारत की उत्तर प्रदेश इकाई द्वारा आज आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर भव्य वाहन रैली एवं झांकी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष सुमित कटियार एवं प्रदेश महामंत्री गोपाल सिंह चाहर ने संयुक्त रूप से किया।

प्रातः 11 बजे गोपेखर की बगिची, नौबस्ता लोहा मंडी से प्रारंभ हुई यह रैली लोहा मंडी चौराहा, जयपुर हाउस, पंचकुड़ियां, तहसील मार्ग और कलेक्ट्रेट होते हुए छीपी टोला के रास्ते बिजलीघर चौराहा पहुंची। वहां स्थित शिवाजी चौक पर कार्यकर्ताओं ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने शिवाजी महाराज के शौर्य, राष्ट्रनिष्ठा और संगठन क्षमता को स्मरण करते हुए उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। सभा को संबोधित करते हुए सुमित कटियार और गोपाल सिंह चाहर ने कहा कि शिवाजी महाराज देश की अस्मिता और स्वाभिमान के प्रतीक हैं। शिवाजी महाराज को भारतीय इतिहास में अद्वितीय सैन्य कौशल, सुरासन और राष्ट्रभक्ति के लिए स्मरण किया जाता है। भारत के इतिहास में उनका योगदान प्रेरणास्रोत है। उन्होंने वर्तमान सामाजिक



और सांस्कृतिक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए संगठन की विचारधारा को मजबूत करने की अपील की।

वक्ताओं ने ‘लव जिहाद’ और धर्मांतरण जैसे मुद्दों का उल्लेख करते हुए समाज से जागरूक रहने का आह्वान किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए गोपाल सिंह चाहर प्रदेश महामंत्री एवं प्रदेश अध्यक्ष सुमित कटियार ने संयुक्त रूप से कहा है कि वीर शिवा हमारे देश का गौरव हैं। आज हम उनके जन्मदिवस के अवसर पर संकल्प लेते हैं कि जिस प्रकार से देश के

अंदर कट्टरपंथियों के द्वारा जिहादी तत्वों के द्वारा लव जिहाद, भूमि जिहाद, जल जिहाद, शूक जिहाद, मूल जिहाद, ब्यूटी पार्लर जिहाद, शिक्षा जेहाद और धर्मांतरण जिहाद जैसे कृत्यों को करने में लिप्त लगे हुए हैं और इससे यह देश में अस्थिरता लाना चाहते हैं और दूसरा यह एक जनसंख्या बढ़ाने के साथ क्षेत्र का भौगोलिक इतिहास बदलना चाहते हैं। आज हम सभी हिंदू वासियों से अपील करते हैं कि सभी हिंदू समाज के लोग अपने परिवार को बढ़ाएं, साथ ही उन्होंने हिंदू समाज से पारिवारिक मूल्यों को सुदृढ़

करने और जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में अधिक संतानों के जन्म का आग्रह भी किया। कार्यक्रम का संचालन महानगर अध्यक्ष हर्ष कटियार ने किया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से रेखा राघव, गीता जैन, विनोद गौतम, जगुण कुमार, रौनक दीक्षित, विकास कुमार, आयुष चाहर, शाह निरपुद खंडेलवाल, अनेक यादव, दीपक राठौड़, अनुराग शर्मा, शिवम यादव, रोहित कर्दम सहित संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी रवि व्यास, नितिन गोस्वामी, दीपक जैन एवं विमल प्रजापति उपस्थित रहे।

## न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर ने 3032 और 3230 TX स्मार्ट ट्रैक्टर का ग्राँड लॉन्च किया

किसानों को 15 ट्रैक्टर डिलीवर किए गए | 20 ट्रैक्टर बुक किए गए।

वाराणसी: खेती के सेक्टर में मॉडर्न टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देते हुए, न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर ने आज वाराणसी के कचहरी में कमिश्नर ऑडिटोरियम में अपने 3032 और 3230 TX स्मार्ट ट्रैक्टर मॉडल को ग्राँड लॉन्च किया। इस मौके पर कंपनी के सीनियर अधिकारी मौजूद थे।

नए मॉडल्स को स्टेट हेड नितेश सचान, स्टेट सर्विस हेड प्रदीप कुमार, कैपिटल फाइनेंस हेड अंशुमान पांडे और विवेक गंगवार, और सीनियर सेल्स मैनेजर पुनीत साहू ने मिलकर लॉन्च किया। इस इवेंट में टेरिरी मैनेजर मनोष त्रिपाठी, विशाल उपाध्याय, ओम प्रकाश यादव, सुनील यादव, विजयपाल यादव, और दूसरे खास मेहमान भी मौजूद थे।

नए मॉडल्स को लेकर किसानों और डीलरों में काफी उत्साह था। लॉन्च के मौके पर कुल 20 ट्रैक्टरों की बुकिंग हुई, जो कंपनी पर किसानों के पक्के भरोसे को दिखाता है। डिलीवरी के बारे में, कंपनी ने बताया कि ट्रैक्टर इस तरह डिलीवर किए गए:



सोनभद्र में 4 ट्रैक्टर मिर्ज़ापुर में 3 ट्रैक्टर कौशांबी में 3 ट्रैक्टर वाराणसी में 3 ट्रैक्टर गाज़ीपुर में 2 ट्रैक्टर कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि 3032 और 3230 TX स्मार्ट मॉडल

मॉडर्न टेक्नोलॉजी, बेहतर माइलेज और हाई परफॉर्मेंस से लैस हैं, जिससे किसानों की प्रोडक्टिविटी काफी बढ़ेगी। प्रोग्राम के आखिर में, किसानों और डीलरों ने नए मॉडल की तारीफ की और भविष्य में भी सहयोग जारी रखने का भरोसा जताया।

## वसंत विशेष काव्यगोष्ठी “फिर से खिल उठा मन” संपन्न

परिवहन विशेष न्यूज

फरीदाबाद - काव्यगिरिमा हिंदी साहित्य मंच (रजि.) के तत्वावधान में आयोजित वसंत विशेष काव्यगोष्ठी का आयोजन हाल ही में ऑनलाइन माध्यम (गूगल मीट) पर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

इस काव्यगोष्ठी का विषय “फिर से खिल उठा मन” रखा गया, जिस पर कवियों ने वसंत ऋतु के उल्लास, नवजीवन, आशा और मानवीय संवेदनाओं को अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रभावशाली अभिव्यक्ति दी।

कार्यक्रम का संचालन मंच की संस्थापिका डॉ. गरिमा भाटी (गौरी) जी द्वारा किया गया, जिन्होंने पूरे सत्र को सहजता, आत्मीयता और साहित्यिक गरिमा के साथ आगे बढ़ाया।

कार्यक्रम का शुभारंभ कवयित्री कविता कोठारी जी द्वारा प्रस्तुत सरस्वती वंदना से हुआ, जिसने वातावरण को भक्तिमय और सृजनात्मक बना दिया।



इसके पश्चात उषा सुद जी, जयप्रकाश सिंह जी, उर्मिला ध्यावाला जी, भगवान दास जी, प्रमोद झा जी, किरण अग्रवाल जी, निराला पाठक जी तथा निधि बोथरा जी ने अपनी भावपूर्ण रचनाओं का पाठ किया।

कविताओं में मन के पुनः खिलने, वसंत की कोमल अनुभूति और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टि का सुंदर चित्रण देखने को मिला। कार्यक्रम का आयोजन एवं समन्वय काव्यगिरिमा हिंदी साहित्य मंच के

सामाजिक मीडिया प्रभारी एवं आयोजक प्रेम ठक्कर (दिकुप्रेमी) द्वारा किया गया। कार्यक्रम के अंत में मंच की ओर से सभी सहभागियों के प्रति आभार व्यक्त किया गया तथा भविष्य में भी ऐसे साहित्यिक आयोजनों को निरंतर आगे बढ़ाने की बात कही गई।

## वाराणसी में संयुक्त पुलिस आयुक्त आलोक प्रियदर्शी का भव्य स्वागत

परिवहन विशेष न्यूज

वाराणसी: वाराणसी के नवनियुक्त संयुक्त पुलिस आयुक्त आलोक प्रियदर्शी के पदभार ग्रहण करने के अवसर पर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिवकुमार गुप्ता के नेतृत्व में व्यापारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत एवं अभिनंदन किया। व्यापारियों ने उन्हें पारंपरिक अंगवस्त्रम एवं एक पौधा भेंट कर सम्मान दिया। उन्होंने उनकी नवनियुक्ति पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर बोलते हुए शिवकुमार गुप्ता ने विश्वास जताया कि प्रियदर्शी के नेतृत्व में वाराणसी में कानून व्यवस्था और भी मजबूत होगी तथा

व्यापारी समुदाय को अधिक सुरक्षित वातावरण प्राप्त होगा। उन्होंने प्रशासन एवं व्यापार संघ के बीच समन्वय बनाए रखने के महत्व पर भी बल दिया। स्वागत कार्यक्रम में व्यापार संघ वाराणसी ग्रामीण के जिला अध्यक्ष शुभम सिंह, मिर्जामुराद व्यापार संघ के महासचिव जितेंद्र सोनकर, रमेश कुमार, प्रदेश युवा महासचिव प्रदीप अग्रहरि, प्रदेश युवा मंत्री बृजेश केसरी, मोरला व्यापार संघ के अध्यक्ष रामधनी यादव आदि उपस्थित रहे। कई दूसरे ट्रैड्स के साथ।



प्रोग्राम का अंत आपसी सहयोग और जनता के हित में काम करने के सामूहिक वादे के साथ हुआ।

## अंतरराष्ट्रीय करुणा साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्थान के अंतर्गत हुआ तीन पुस्तकों का लोकार्पण

परिवहन विशेष न्यूज

लखनऊ। विगत दिवस केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय गोमतीनगर के परिसर में खादी एवं ग्रामोद्योग महोत्सव के मंच पर अंतरराष्ट्रीय करुणा साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्थान के तत्वाधान में डॉ आर्यावती सरोज 'आर्या' की दो पुस्तकों काव्य संग्रह - “निश्चेतन सिलिका” और बाल कहानी संग्रह “चंद्रयान” तथा रवीन्द्र नाथ तिवारी के काव्य संग्रह - “राष्ट्र चिन्तन” का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के पूजन, दीप प्रज्वलन, माल्यार्पण और उनकी वंदना से की गई। सरस्वती वन्दना कवयित्री निशा सिंह 'नवल' ने किया। अध्यक्ष नरेन्द्र भूषण तथा विशिष्ट अतिथि महेंद्र भीष्म ने



पुस्तक के सम्बन्ध में वक्तव्य दिया। यह कार्यक्रम वरिष्ठ साहित्यकार नरेन्द्र भूषण की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ साहित्यकार महेंद्र भीष्म, हरिश्चंद्र निशांत रवीन्द्र नाथ तिवारी, निर्भय नारायण गुप्त, के पी त्रिपाठी पुंज, गिरधर खरे, अष्टाना महेश

प्रकाश विशिष्ट अतिथि के रूप में मंचस्थ रहे। श्रीमती शरद सिंह, शरद मिश्र सिन्धु, अरविंद रस्तोगी, रवि कांत पांडेय, अनिल कुमार जैसवाल 'बेअदब लखनवी', मनमोहन बाराकोटी, शशि नारायण त्रिपाठी, आशुतोष तिवारी 'आशु', हिमांशु सक्सेना 'अर्शा लखनवी'

करुणा पाण्डेय, राधा बिष्ट, मनस्वी श्वेता, शीला वर्मा मीरा, अलका गुप्ता 'प्रियदर्शनी', पायल लक्ष्मी सोनी, सरला शर्मा 'आस्मां', निशा सिंह 'नवल' और रेनु द्विवेदी ने शानदार काव्यपाठ किया, जिस पर पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गुंजाता रहा। कार्यक्रम का बेहतरीन संचालन रेनु द्विवेदी ने किया। सभी मंचीय अतिथियों को माल्यार्पण एवं शाल्यार्पण कर व कलम देकर उन्हें सम्मानित किया गया। आमंत्रित सभी कवि-कवयित्रियों को माल्यार्पण एवं कलम भेंटकर उन्हें सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में संस्थान की संस्थापिका एवं अध्यक्ष डॉ आर्यावती सरोज 'आर्या' ने सभी आगंतुकों का हार्दिक आभार व्यक्त किया।

## ब्रेकिंग न्यूज | रायबरेली

रायबरेली PWD की 1600 मीटर सड़क पर बवाल: ग्रामीणों का हंगामा, जेई-ठेकेदार पर भ्रष्टाचार के आरोप

सदर क्षेत्र के राही ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सभा ताला बसाढ़ में पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाई रही सड़क

मानकों के विपरीत निर्माण का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने मौके पर जोरदार विरोध प्रदर्शन

किया और विभागीय जूनियर इंजीनियर (जेई) व ठेकेदार पर खुलेआम भ्रष्टाचार का आरोप जड़ दिया।

यह सड़क शिवेन्द्र सिंह के घर के पास से शुरू होकर नेशनल हाईवे स्थित विराट ढाबा तक बनाई जा रही है।

ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण शुरू होते ही गुणवत्ता की पोल खुल गई।

ग्रामीणों के आरोप क्या हैं? घटिया सामग्री का

इस्तेमाल सड़क की मोटाई मानक से कमसही तरीके से कंपैक्शन नहीं

कई जगहों पर शुरुआती दरारें, निर्माण के दौरान जेई की गैर मौजूदगी, एक ग्रामीण ने आरोप लगाया,

सड़क डालते समय सामग्री का सही अनुपात नहीं रखा गया। जेई साहब साइट पर नजर नहीं आए।

ठेकेदार और अधिकारी मिलकर लाखों का खेल कर रहे हैं। सुबह 7 बजे सड़क निर्माण स्थल पर हंगामा

ग्रामीणों ने निर्माण स्थल पर इकट्ठा होकर नारेबाजी की। उनकी मांग है

जेई और ठेकेदार को तत्काल हटाना जाए। निर्माण कार्य की निष्पक्ष जांच हो मानक के अनुसार दोबारा सड़क बनाई जाए

ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर गुणवत्ता में सुधार नहीं आता तो वे काम रुकवाने के साथ डीएम को ज्ञापन देंगे।

ग्रामीणों का आरोप है कि महज 1600 मीटर सड़क में भी करोड़ों रुपये का बजट दिखाया जा रहा है,

जो सीधे-सीधे भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है। स्थानीय स्तर पर जेई और ठेकेदार दोनों के मौके से गायब रहने की भी बात सामने आई है।

रायबरेली में PWD पर पहले भी उठ चुके हैं बवाल

बसाढ़ का यह मामला जिले में पीडब्ल्यूडी निर्माण कार्यों को लेकर उठती रही शिकायतों की एक और कड़ी बनता जा रहा है।

सत्यम मिश्रा सोशल मीडिया विशेषज्ञ उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड

# भारतीय ज्ञान परंपरा और विज्ञान शिक्षा : सोच-समझकर आगे बढ़ने की आवश्यकता



विजय गर्ग



भारतीय परंपरा में ज्ञान को समग्र रूप में देखा गया। वेद और उपनिषद में ब्रह्मांड, प्रकृति, चेतना और जीवन के रहस्यों पर गहन विचार मिलता है। आचार्य चरक और सुश्रुत ने आयुर्वेद और शल्य चिकित्सा में वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया। आर्यभट्ट ने खगोल विज्ञान और गणित में ऐसे सिद्धांत दिए जो आधुनिक विज्ञान की नींव से मेल खाते हैं।

भारत की ज्ञान परंपरा हजारों वर्षों पुरानी है। यहाँ शिक्षा केवल ज्ञान को प्रदान करने का माध्यम नहीं थी, बल्कि जीवन को समझने, प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाने और मानव कल्याण की दिशा में आगे बढ़ने का साधन थी। आज जब विज्ञान और तकनीक का युग है, तब यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या हमारी आधुनिक विज्ञान शिक्षा भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़कर आगे बढ़ रही है या उससे कटती जा रही है।

प्रकृति का अवलोकन, औषधीय पौधों का अध्ययन, स्थानीय पर्यावरण की समझ। 3. विज्ञान और नैतिकता का संतुलन विज्ञान का उद्देश्य मानव कल्याण होना चाहिए, केवल तकनीकी प्रगति नहीं। 4. प्रश्न पूछने की संस्कृति उपनिषदों की संवाद परंपरा जिज्ञासा और चिंतन को बढ़ावा देती है। विज्ञान शिक्षा में परंपरा का समावेश कैसे हो? पाठ्यक्रम में भारतीय वैज्ञानिकों और परंपरागत ज्ञान को शामिल किया जाए। योग, आयुर्वेद, पर्यावरणीय ज्ञान को वैज्ञानिक दृष्टि से प्रस्तुत किया जाए। स्थानीय ज्ञान प्रणालियों का दस्तावेजीकरण और अध्ययन प्रयोगात्मक एवं प्रोजेक्ट आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना। विज्ञान को सामाजिक समस्याओं के समाधान से जोड़ा जाए। सावधानी भी आवश्यक है।

हर परंपरागत विचार वैज्ञानिक नहीं होता। इसलिए: प्रमाण और परीक्षण आवश्यक हैं वैज्ञानिक पद्धति का पालन अनिवार्य है और विवेक को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। आगे की राह भारत यदि ज्ञान महाशक्ति बनना चाहता है, तो उसे अपनी जड़ों से जुड़े रहते हुए आधुनिक विज्ञान की दिशा में आगे बढ़ना होगा। भारतीय ज्ञान परंपरा हमें सोचने, प्रश्न करने और प्रकृति के साथ संतुलन में जीने की प्रेरणा देती है, जबकि आधुनिक विज्ञान हमें खोज, नवाचार और तकनीकी प्रगति की दिशा दिखाता है। दोनों का समन्वय ही भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। विज्ञान तभी सार्थक है जब वह ज्ञान, संवेदनशीलता और मानवता के साथ जुड़ा हो—और यही भारतीय ज्ञान परंपरा का मूल संदेश है। डॉ. विजय गर्ग सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलौट पंजाब

प्रकृति का अवलोकन, औषधीय पौधों का अध्ययन, स्थानीय पर्यावरण की समझ। 3. विज्ञान और नैतिकता का संतुलन विज्ञान का उद्देश्य मानव कल्याण होना चाहिए, केवल तकनीकी प्रगति नहीं। 4. प्रश्न पूछने की संस्कृति उपनिषदों की संवाद परंपरा जिज्ञासा और चिंतन को बढ़ावा देती है। विज्ञान शिक्षा में परंपरा का समावेश कैसे हो? पाठ्यक्रम में भारतीय वैज्ञानिकों और परंपरागत ज्ञान को शामिल किया जाए। योग, आयुर्वेद, पर्यावरणीय ज्ञान को वैज्ञानिक दृष्टि से प्रस्तुत किया जाए। स्थानीय ज्ञान प्रणालियों का दस्तावेजीकरण और अध्ययन प्रयोगात्मक एवं प्रोजेक्ट आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना। विज्ञान को सामाजिक समस्याओं के समाधान से जोड़ा जाए। सावधानी भी आवश्यक है।



संपादकीय

चिंतन-मनन

## बांग्लादेश कैबिनेट में हिंदू मंत्रियों के होने के निहितार्थ



बाँते कुछ महीनों में 11 हिंदुओं के साथ हुई निर्मम बर्बरता ने बांग्लादेश की न सिर्फ थू थू करवाई बल्कि दशकों से मधुर संबंधों को भी पटरी से उतार दिया था। इसको लेकर दोनों मुल्कों में तल्लियां बनी हुई थीं। रहमान जानते हैं अगर माहौल ऐसा ही बरकरार रहा, तो रिश्तों की दूरियां घटने वाली नहीं? ऐसी अखरती दुश्चारियों पर गौर करते हुए ही रहमान ने अपनी कैबिनेट में हिंदू समुदाय से ताल्लुक रखने वाले सांसदों को अहम औहदे सौंपे ताकि रिश्तों में फिर से नरमी लाई जा सके। भारत ने भी उनके निर्णय को सराहा है।

डा. रमेश ठाकुर

पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में तारिक रहमान के रूप में नई सरकार शपथ ले चुकी है। खास बात ये है रहमान के नेतृत्व वाली नई सरकार में दो हिंदू सांसदों को मंत्री बनाया गया है। उनके इस निर्णय को भारत के साथ प्रत्यक्ष रूप से बिगड़े संबंधों को सुधारने की पहल के रूप में समूची दुनिया देख रही है। इस कदम से चीन-पाकिस्तान चिड़ें भी हैं। वो नहीं चाहते कि बांग्लादेश भारत या उनसे वास्ता रखने लोगों को तवज्जो दे लेकिन, तारिक रहमान ने उनके नापाक मंसूबों को धता बलाते हुए, बड़ी सूझ बूझ से कदम आगे बढ़ाया। बाँते कुछ महीनों में 11 हिंदुओं के साथ हुई निर्मम बर्बरता ने बांग्लादेश की न सिर्फ थू थू करवाई बल्कि दशकों से मधुर संबंधों को भी पटरी से उतार दिया था। इसको लेकर दोनों मुल्कों में तल्लियां बनी हुई थीं। रहमान जानते हैं अगर माहौल ऐसा ही बरकरार रहा, तो रिश्तों की दूरियां घटने वाली नहीं? ऐसी अखरती दुश्चारियों पर गौर करते हुए ही रहमान ने अपनी कैबिनेट में हिंदू समुदाय से ताल्लुक रखने वाले सांसदों को अहम औहदे सौंपे ताकि रिश्तों में फिर से नरमी लाई जा सके। भारत ने भी उनके निर्णय को सराहा है।

बाँते कुछ महीनों में 11 हिंदुओं के साथ हुई निर्मम बर्बरता ने बांग्लादेश की न सिर्फ थू थू करवाई बल्कि दशकों से मधुर संबंधों को भी पटरी से उतार दिया था। इसको लेकर दोनों मुल्कों में तल्लियां बनी हुई थीं। रहमान जानते हैं अगर माहौल ऐसा ही बरकरार रहा, तो रिश्तों की दूरियां घटने वाली नहीं? ऐसी अखरती दुश्चारियों पर गौर करते हुए ही रहमान ने अपनी कैबिनेट में हिंदू समुदाय से ताल्लुक रखने वाले सांसदों को अहम औहदे सौंपे ताकि रिश्तों में फिर से नरमी लाई जा सके। भारत ने भी उनके निर्णय को सराहा है।

बाँते कुछ महीनों में 11 हिंदुओं के साथ हुई निर्मम बर्बरता ने बांग्लादेश की न सिर्फ थू थू करवाई बल्कि दशकों से मधुर संबंधों को भी पटरी से उतार दिया था। इसको लेकर दोनों मुल्कों में तल्लियां बनी हुई थीं। रहमान जानते हैं अगर माहौल ऐसा ही बरकरार रहा, तो रिश्तों की दूरियां घटने वाली नहीं? ऐसी अखरती दुश्चारियों पर गौर करते हुए ही रहमान ने अपनी कैबिनेट में हिंदू समुदाय से ताल्लुक रखने वाले सांसदों को अहम औहदे सौंपे ताकि रिश्तों में फिर से नरमी लाई जा सके। भारत ने भी उनके निर्णय को सराहा है।

## विश्व सामाजिक न्याय दिवस : समानता, अधिकार और अवसरों की दिशा में वैश्विक संकल्प

-सुनील कुमार महला

वैश्वे तो 20 फरवरी को कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण दिवस ( अरुणाचल प्रदेश स्थापना दिवस तथा मिजोरम स्थापना दिवस ) मनाए जाते हैं, लेकिन इसी दिन विश्व सामाजिक न्याय दिवस ( वर्ल्ड डे आफ सोशल जस्टिस ) भी मनाया जाता है। दरअसल, यह दिवस सामाजिक समानता, मानवाधिकार, रोजगार के अवसर और न्यायपूर्ण संभव हो सकत है। आज दुनिया भर में गरीबी, बेरोजगारी, लैंगिक असमानता, मानवाधिकार हनन और सामाजिक भेदभाव जैसे मुद्दे मौजूद हैं और इस दिवस को मनाने के पीछे मुख्य कारण इन सब के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। उल्लेखनीय है कि इस दिन को बढ़ावा देने में अंतरराष्ट्रीय श्रम संघटना ( आईएलओ ) की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जो 'सभी के लिए सम्मानजनक काम और सामाजिक सुरक्षा' की अवधारणा को मजबूत करता है। कहना गलत नहीं होगा कि आज पूरी दुनिया में आर्थिक असमानता बढ़ती चली जा रही है और सामाजिक विभाजन देखने को मिल रहा है, ऐसे में यह दिवस आर्थिक समानता के साथ ही साथ सामाजिक विभाजन को कम करने पर जोर देता है। दूसरे शब्दों में कहें तो आज अमीर और गरीब के बीच की खाई खतरनाक स्तर तक बढ़ रही है, ऐसे में विश्व में शांति स्थापित करना एक टेढ़ी खीर नजर आता है। कहना गलत नहीं होगा कि अगर किसी समाज में बेरोजगारी, गरीबी और भेदभाव है, तो वहाँ गृहयुद्ध या अपराध की संभावना सबसे ज्यादा होती है। अब 'डिजिटल डिवाइड' पर नया फोकस हो रहा है और पिछले कुछ सालों से, यह दिन सिर्फ रोटी-कपड़ा-मकान तक सीमित नहीं रहा है। अब इस दिवस का एक बड़ा हिस्सा 'डिजिटल सोशल जस्टिस' है। दरअसल, यह एक कठु सत्य होने के साथ ही साथ एक तथ्य है कि आज भी, संचार क्रांति, एआइ के इस दौर में दुनिया की एक तिहाई आबादी के पास इंटरनेट सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।

इसे घोषित किया, लेकिन इसकी असली नींव 1995 के कोपेनहेगन ( डेनमार्क ) सम्मेलन में पड़ी थी। वहाँ दुनिया के नेताओं ने पहली बार माना था कि गरीबी मिटाना सिर्फ दान का काम नहीं, बल्कि मानवाधिकारों की रक्षा का काम है। किसी समाज में कानून का पालन होना तथा वहाँ विभिन्न संसाधनों जैसे कि पैसा, स्वास्थ्य, शिक्षा का समान वितरण होना, तभी उस समाज में सामाजिक न्याय की अवधारणा संभव हो सकती है। आज दुनिया के 60% से ज्यादा मजदूर बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट या सामाजिक सुरक्षा के काम करते हैं। कहना गलत नहीं होगा कि उनके लिए हक माँगना ( सामाजिक न्याय ) ही इस दिन का असली उद्देश्य बन गया है। आज दुनिया भर में गरीबी, बेरोजगारी, लैंगिक असमानता, मानवाधिकार हनन और सामाजिक भेदभाव जैसे मुद्दे मौजूद हैं और इस दिवस को मनाने के पीछे मुख्य कारण इन सब के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। उल्लेखनीय है कि इस दिन को बढ़ावा देने में अंतरराष्ट्रीय श्रम संघटना ( आईएलओ ) की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जो 'सभी के लिए सम्मानजनक काम और सामाजिक सुरक्षा' की अवधारणा को मजबूत करता है। कहना गलत नहीं होगा कि आज पूरी दुनिया में आर्थिक असमानता बढ़ती चली जा रही है और सामाजिक विभाजन देखने को मिल रहा है, ऐसे में यह दिवस आर्थिक समानता के साथ ही साथ सामाजिक विभाजन को कम करने पर जोर देता है। दूसरे शब्दों में कहें तो आज अमीर और गरीब के बीच की खाई खतरनाक स्तर तक बढ़ रही है, ऐसे में विश्व में शांति स्थापित करना एक टेढ़ी खीर नजर आता है। कहना गलत नहीं होगा कि अगर किसी समाज में बेरोजगारी, गरीबी और भेदभाव है, तो वहाँ गृहयुद्ध या अपराध की संभावना सबसे ज्यादा होती है। अब 'डिजिटल डिवाइड' पर नया फोकस हो रहा है और पिछले कुछ सालों से, यह दिन सिर्फ रोटी-कपड़ा-मकान तक सीमित नहीं रहा है। अब इस दिवस का एक बड़ा हिस्सा 'डिजिटल सोशल जस्टिस' है। दरअसल, यह एक कठु सत्य होने के साथ ही साथ एक तथ्य है कि आज भी, संचार क्रांति, एआइ के इस दौर में दुनिया की एक तिहाई आबादी के पास इंटरनेट सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।



तकनीक के इस दौर में इंटरनेट तक पहुंच न होना भी अब एक बड़ा 'सामाजिक अन्याय' माना जाता है, क्योंकि इसके बिना शिक्षा और रोजगार के अवसर छिन जाते हैं। वास्तव में सामाजिक न्याय तभी संभव हो सकता है जब समाज में शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा की नींव मजबूत हो। किसी भी समाज में समावेशी विकास शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षा की नींव मजबूत करके ही संभव हो सकता है। लैंगिक समानता, सामाजिक समावेशन, गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना, मानवाधिकार और समानता को बढ़ावा देना, आज पूरे विश्व समाज की अहम आवश्यकता है। बहरहाल, यदि हम यहाँ पर सरल शब्दों में कहें तो इस दिवस का मूल

संदेश है - 'ऐसा समाज बनाना जहाँ हर व्यक्ति को बराबरी, सम्मान और अवसर मिले।' बहरहाल, पाठकों को बताता चलूँ कि पिछले साल यानी कि वर्ष 2025 में इस दिवस की थीम 'सामाजिक न्याय के लिए बाधाओं को दूर करना' और अवसरों को उजागर करना' रखी गई थी तथा इस वर्ष यानी कि वर्ष 2026 में यह 'साझा भविष्य के लिए असमानताओं को पाटना' रखी थी है। कहना गलत नहीं होगा कि यह थीम यह स्पष्ट करती है कि आधुनिक दौर में केवल पुरुषों को सुलझाना काफी नहीं है, बल्कि डिजिटल और तकनीकी युग में पैदा हो रही नई असमानताओं को भी खत्म करना जरूरी है। निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि विश्व सामाजिक न्याय दिवस केवल एक वार्षिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह एक वैश्विक संकल्प है। यह दिवस हमें यह याद दिलाता है कि शांति और सुरक्षा तभी संभव है जब हर व्यक्ति को उसकी जाति, लिंग, धर्म या आर्थिक स्थिति के भेदभाव के बिना न्याय मिले। मतलब यह है कि समानता का अधिकार आज की आवश्यकता है। सामाजिक न्याय केवल सरकारों का काम नहीं है, बल्कि यह समाजों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों और हम नागरिकों की भी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम एक समावेशी दुनिया बनाने में अपना योगदान दें। अंत में यदि हम सरल शब्दों में कहें तो जब तक समाज के सबसे कमजोर वर्ग को मुख्यधारा में शामिल नहीं किया जाता, तब तक वैश्विक विकास अधूरा है।

## शक की बीमारी : प्रेम से हत्या तक का खौफनाक सफर

शम्भु शरण सत्यार्थी

एक अखबार की सुखी है— "हफ्ते भर तक काट-काटकर जलता रहा पत्नी का शव"। यह पंक्ति पढ़ते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सोच पाना भी कठिन है कि कोई इंसान, जो कभी किसी औरत को अपनी कहकर दुनिया से लड़ने का दावा करता था, वही इंसान शक की आग में इतना अंधा हो जाए कि उसे मारने के बाद भी उसके शव को टुकड़ों में काटकर जलता रहे, यह उस मानसिक बीमारी की भयावह परिणति है जिसे हम सामान्य भाषा में शक कहते हैं। इसी की यह घटना हमें भीतर तक झकझोरती है। एक रिटायर्ड रेलकर्मी, अपनी पत्नी पर यह शक करने लगता है कि उसके संबंध किसी और से हैं। यह शक धीरे-धीरे उसके दिमाग में घर करता गया, बढ़ता गया, और अंततः उसने उसी स्त्री को हत्या कर दी, जो उससे उम्र में 32 साल छोटी थी, जो उसके घर की रसोई से लेकर उसके बिस्तर तक का हिस्सा थी। हत्या के बाद भी उसका पागलपन शांत नहीं हुआ—

वह शक को काटता रहा, जलता रहा, ताकि "सबूत" मिल जाए। यह घटना कोई अपवाद नहीं है। यह हमारे समाज में फैलती उस मानसिक हिंसा का चरम उदाहरण है, जहाँ शक प्यार को निगल जाता है और रिश्ता कब कबमें बदल जाता है, पता ही नहीं चलता। शक : एक धीमा जहर शक कोई एक दिन में पैदा नहीं होता। यह धीरे-धीरे पनपता है—जैसे दीमक। शुरू में यह छोटे सवालियों के रूप में आता है— फोन देर से क्यों उठाया? इतनी देर किससे बात कर रही थी? तुम आज बदली-बदली क्यों लग रही हो? शुरुआत में ये सवाल सामान्य लगते हैं, समाज इन्हें प्यार की चिंता कहकर जायज ठहरा देता है लेकिन यहाँ से समस्या जन्म लेती है। जब सवाल भरोसे से नहीं, निरंत्रण की भावना से पूछे जाने लगें, तब रिश्ता बीमार होने लगता है। शक का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि यह तर्क नहीं सुनता। जितना समझाओ, उतना ही शक बढ़ता है, सफाई को भी अपराध मान लिया जाता है। धीरे-

धीरे शक करने वाला खुद को जज, वकील और जल्लाद—तीनों मानने लगता है। पति-पत्नी का रिश्ता और पुरुष अहंकार भारतीय समाज में पति-पत्नी का रिश्ता आज भी समानता से ज्यादा स्वामित्व की भावना से देखा जाता है, खासकर पुरुषों के मामले में। पत्नी को अक्सर इज्जत, मर्यादा और घर की आन से जोड़ दिया जाता है, ऐसे में यदि पुरुष के मन में जरा-सा भी शक पैदा हो जाए, तो वह इसे सिर्फ निजी भावना नहीं मानता, बल्कि अपनी मरदांगी और सम्मान पर हमला समझने लगता है। इसी की घटना में भी यही दिखता है। आरोपी को शक था कि पत्नी किसी और से बात करती है। सवाल यह नहीं कि शक सही था या गलत—सवाल यह है कि क्या किसी इंसान को शक के आधार पर दूसरे की जान लेना का हक मिल जाता है ? लेकिन शक की बीमारी में इंसान यही मान लेता है कि वह जो कर रहा है, वह न्याय है। शक और मानसिक हिंसा हत्या अंतिम चरण है। उससे पहले लंबा दौर

चलता है मानसिक हिंसा का। बार-बार शक करना, फोन चेक करना, आवाज ऊँची करना, चरित्र पर सवाल उठाना, अलग-थलग करना, डर के माहौल में जीने को मजबूर करना, बहुत-सी औरतें इसी दौर में घुट-घुट कर मरने लगती हैं। उनका शरीर जीवित होता है, लेकिन आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और खुशी धीरे-धीरे खत्म हो जाती है। कई बार यही मानसिक हिंसा औरतों को आत्महत्या तक धकेल देती है। और कई बार यही हिंसा पुरुष को हत्या तक ले जाती है। क्या शक सिर्फ पुरुष करते हैं ? नहीं, शक एक मानसिक बीमारी है, जिसका लिंग नहीं होता। कई मामलों में पत्नियों भी पति पर शक करती हैं—अफेयर का शक, कमाई छुपाने का शक, दूसरी औरतों से संबंध का शक, कुछ मामलों में यह शक इतना उग्र हो जाता है कि पत्नी पति को हत्या कर देती है या किसी और से करवा देती है लेकिन आँकड़े बताते हैं कि शक के नाम पर होने वाली घरेलू हत्याओं में पीड़ितों की संख्या ज्यादातर औरतों की है। कारण साफ़ है—सत्ता का

असंतुलन, पुरुष के पास शारीरिक ताकत, सामाजिक समर्थन और नियंत्रण अधिक होता है। शक क्यों बढ़ता है ? शक की जड़ें कई स्तरों पर होती हैं। असुरक्षा, खूद को कमतर महसूस करना, स्वामित्व की भावना पत्नी को अपनी चीज समझना, समाज की पितृसत्तात्मक सोच, औरत को शक के कटघरे में खड़ा करना, संवाद की कमी—बात करने की बजाय निगरानी करना। सोशल मीडिया और फोन, हर मैसेज को शक की नजर से देखना, विडंबना यह है कि आज के समय में तकनीक ने शक को और आसान बना दिया है। ऑनलाइन स्टेटस, व्हाट्सएप, कॉल हिस्ट्री—सब शक को खाद देने लगे हैं। शक का अंत : या तो मौत, या टूटन शक का रिश्ता कभी स्वस्थ अंत तक नहीं पहुँचता। इसका अंत दो ही तरह से होता है या तो रिश्ता टूट जाता है या कोई एक टूट जाता है। इसी की घटना में अंत हत्या के रूप में हुआ। लेकिन देश में हर दिन सैकड़ों रिश्ते ऐसे हैं, जो शक की आग में जल रहे हैं—बिना खबर बने, बिना सुखी बनें।

समाधान कहाँ है ? शक को अपराध बनाने से पहले रोकना जा सकता है, रिश्तों में संवाद को प्राथमिकता देकर, प्यार को नियंत्रण से अलग समझ कर, मानसिक स्वास्थ्य को गंभीरता से लेकर, पुरुषों को यह सिखाकर कि शक मरदांगी नहीं, कमजोरी है, औरतों को यह भरोसा देकर कि वे अकेली नहीं हैं। सबसे जरूरी बात शक को सामान्य मत बनाइए, जिस दिन समाज शक को प्यार का नाम देना बंद करेगा, उसी दिन ऐसी हत्याओं की जड़ कटनी शुरू होगी, इसी की वह औरत अब इस दुनिया में नहीं है लेकिन उसका सवाल हमारे सामने है—क्या प्यार शक के साथ जिंदा रह सकता है ? जवाब साफ़ है—नहीं, जहाँ भरोसा नहीं, वहाँ प्यार नहीं और जहाँ शक है, वहाँ देर-सबेर हिंसा है। यह घटना नहीं बल्कि उस बीमारी पर है, जो चुपचाप हमारे घरों में पल रही है। अगर आज भी हमने इसे गंभीरता से नहीं लिया तो अगली सुखी किसी और घर की होगी—किसी और औरत की, किसी और रिश्ते की।

# रेवड़ी संस्कृति बनाम कल्याणकारी राज्य - सुप्रीम कोर्ट की फिर सख्त टिप्पणी- मुफ्तखोरी, खैरात की संस्कृति: -लोकतंत्र, अर्थव्यवस्था और संवैधानिक दायित्व के बीच संतुलन की अनिवार्यता

रेवड़ी संस्कृति पर नियंत्रण केवल कानून का विषय नहीं, बल्कि राजनीतिक इच्छाशक्ति, नागरिक जागरूकता और आर्थिक विवेक का सम्मिलित परिणाम होगा। क्या संसाधनों का उपयोग उत्पादक परिणामों में हो रहा है या उपभोग में? क्या करदाताओं के धन का उपयोग पारदर्शी और न्यायसंगत है? क्या भविष्य की पीढ़ियों पर ऋण का बोझ अनावश्यक रूप से डाला जा रहा है? - एडवोकेट किशन सनमुखादस भावनांनी गोंदिया महाराष्ट्र

**गोंदिया** - वैश्विक स्तर पर भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहाँ 142.6 करोड़ से अधिक नागरिकों की आकांक्षाएँ, आवश्यकताएँ और अधिकार एक जटिल राजनीतिक-आर्थिक ढांचे के माध्यम से संचालित होते हैं। लोकतांत्रिक प्रतियोगिता स्वाभाविक है, परंतु जब यह प्रतियोगिता विकासवादी दृष्टि के स्थान पर अल्पकालिक लोक लुभावन वादों में बदल जाती है, तब उसके दूरगामी परिणाम राष्ट्र के आर्थिक स्वास्थ्य और सामाजिक संरचना दोनों पर पड़ते हैं। हाल के वर्षों में चुनावी मौसम में मुफ्त सुविधाओं, बिजली, पानी, नकद हस्तान्तरण, लैपटॉप साइकिल इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएँ, उपभोक्ता वस्तुएँ, परिवहन, उपकरण विद्यार्थी अनेक मुफ्त वॉटनें की घोषणाओं ने रेवड़ी संस्कृति को एक प्रमुख राष्ट्रीय बहस का विषय बना दिया है। यह बहस केवल राजनीतिक विमर्श नहीं है, बल्कि संविधान, वित्तीय अनुशासन, करदाताओं के अधिकार और भावी पीढ़ियों के आर्थिकसुरक्षा से जुड़ा प्रश्न बन चुकी है। अभी फिर से एक बार गुरुवार दिनांक 19 फरवरी 2026 को भारत की सुप्रीम कोर्ट में तीन सदस्यीय पीठ, सीजेआई सुर्यकांत, जस्टिस जयमाल्य बागची और जस्टिसविपुल कुमार पंचोली ने तमिलनाडु विधुत वितरण निगम के मामले की सुनवाई के दौरान मुफ्त बिजली की संस्कृति पर कठोर टिप्पणी की। अदालत ने स्पष्ट कहा कि उपभोक्ता क्रांति वित्तीय स्थिति का परीक्षण किए बिना सार्वभौमिक रूप से मुफ्त बिजली

देना राज्य के आर्थिक विकास को बाधित कर सकता है। एडवोकेट किशन सनमुखादस भावनांनी गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता है कि न्यायालय की यह टिप्पणी केवल एक राज्य तक सीमित नहीं थी; यह समग्र नीति-दृष्टि पर प्रश्नचिह्न था। अदालत ने इंगित किया कि जब राज्य पहले से ऋणग्रस्त हो और विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन सीमित हों, तब खैरात आधारित राजनीति वित्तीय अनुशासन को कमजोर करती है और दीर्घकालीन बुनियादी निवेशों, जैसे आधारभूत संरचना, स्वास्थ्य शिक्षा को प्रभावित करती है। 121 जनवरी 2026 को भी शोध न्यायालय ने इस विषय को अत्यंत महत्वपूर्ण करार देते हुए लंबित विचारकों की शीर्ष सुनवाई की आवश्यकता पर बल दिया था। याचिकाकर्ता ने देश पर बढ़ते सार्वजनिक ऋण लगभग 250 लाख करोड़ रूपए की ओर ध्यान आकृष्ट किया। न्यायालय ने स्वीकार किया कि नीति-निर्णय का क्षेत्र कार्यपालिका का है, परंतु यह भी पूछा कि क्या राज्य के राज्यस्व का एक सुनिश्चित हिस्सा केवल विकास कार्यों के लिए सुरक्षित नहीं होना चाहिए? यह प्रश्न संघीय ढांचे के भीतर वित्तीय उत्तरदायित्व और जनहित के संतुलन का मूल प्रश्न है।

साथियों बात अगर हम न्यायालय की टिप्पणियों को गहराई से समझने की करें तो उसका एक केंद्रीय बिंदु था कल्याणकारी योजनाओं और चुनावी प्रोबिज को बीच अंतर। संविधान के नीति निर्देशक तत्व राज्य को शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का दायित्व सौंपते हैं। यदि राज्य निर्धन या वंचित वर्गों को मुफ्त शिक्षा या स्वास्थ्य सुविधा देता है, तो वह संवैधानिक दायित्व का निर्वहन है। किंतु जब बिना लक्षित पहचान के, बिना वित्तीय क्षमता के आकलन के, व्यापक स्तर पर मुफ्त वस्तुओं का वितरण केवल चुनावी लाभ हेतु किया जाए, तब वह नीति-आधारित कल्याण नहीं बल्कि अल्पकालिक राजनीतिक निवेश प्रतीत होता है। अदालत ने रोजगार को प्राथमिकता देने की आवश्यकता रेखांकित करते हुए कहा कि उत्पादक क्षमता को बढ़ाने वाली नीतियाँ ही दीर्घकालीन समाधान हैं।

साथियों बात अगर हम आर्थिक दृष्टि इस मुद्दे को समझने की करें तो रेवड़ी संस्कृति का सबसे बड़ा प्रभाव राजकोषीय घाटे और सार्वजनिक ऋण पर पड़ता है। राज्यों का बड़ा हिस्सा पहले ही वेतन, पेंशन और व्याज भुगतान में खर्च हो जाता है। यदि अतिरिक्त संसाधन मुफ्त योजनाओं में लगाए जाते हैं, तो पूंजीगत व्यय सड़क, जल प्रबंधन, ऊर्जा ढांचा, औद्योगिक क्लस्टर के लिए संसाधन घटते हैं। इससे रोजगार सृजन की गति धीमी होती है और कराधान का आधार भी सीमित रहता है। एक दुष्परिणाम है: कम निवेश कम उत्पादन, कम राज्यस्व, अधिक उधारी और अधिक लोकलुभावन घोषणाएँ। न्यायालय द्वारा परजीवी मानसिकता की आशंका इसी आर्थिक तर्क से जुड़ी है, यदि नागरिकों को उत्पादक अवसरों के स्थान पर अनुदान आधारित निर्भरता की ओर प्रेरित किया जाए, तो श्रम भागीदारी और नवाचार दोनों प्रभावित हो सकते हैं।

साथियों बात अगर हम लोकतांत्रिक विमर्श का एक अन्य पहलु चुनावी समानता और निष्पक्षता है इसको समझने की करें तो, यदि राजनीतिक दल करदाताओं के धन से भविष्य में दी जाने वाली मुफ्त सुविधाओं का वादा कर मतदाताओं को प्रभावित करते हैं, तो क्या यह चुनावी प्रतिस्पर्धा की नैतिक सीमा को उल्लंघन है? चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों में घोषणापत्रों की पारदर्शिता की बात कही गई है, परंतु उनके वित्तीय स्रोत और व्यावहारिकता का स्वतंत्र मूल्यांकन अनिवार्य नहीं है। इस संदर्भ में न्यायालय का यह संकेत महत्वपूर्ण है कि गंभीर मामलों को तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा, ताकि व्यापक संवैधानिक प्रश्नों पर स्पष्टता आए। रेवड़ी संस्कृति का सामाजिक आयाम भी उतना ही महत्वपूर्ण है। भारत में ऐतिहासिक रूप से सामाजिक- आर्थिक असमानताएँ रही हैं। कल्याणकारी योजनाएँ सामाजिक न्याय का उपकरण रही हैं, मिड-डे मील, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, छात्रवृत्ति, मनरेगा जैसे कार्यक्रमों ने गरीबी उन्मूलन में



योगदान दिया है। इसलिए किसी भी बहस में यह सावधानी आवश्यक है कि वास्तविक कल्याणकारी योजनाओं को प्रोबिज कहकर खारिज न किया जाए। न्यायालय ने भी शिक्षा और स्वास्थ्य को संवैधानिक दायित्व के रूप में स्पष्ट किया। इसलिए मूल प्रश्न यह है कि लक्षित, आवश्यकता-आधारित, पारदर्शी और वित्तीय रूप से टिकाऊ योजनाओं और सार्वभौमिक, अस्थायी, चुनावी लाभ वाली योजनाओं को बीच रेखा कैसे खींची जाए। यदि इस प्रवृत्ति को नियंत्रित करने हेतु कठोर कानून बनाने की बात हो, तो उसका उद्देश्य प्रतिबंध मात्र नहीं बल्कि संतुलन स्थापित करना होना चाहिए। संभावित कानून का नाम हो सकता है, राष्ट्रीय राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं चुनावी लोकलुभावन व्यय विनियमन अधिनियम। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक चुनावी घोषणा के लिए अनिवार्य वित्तीय स्रोत-प्रमाण, स्वतंत्र आर्थिक मूल्यांकन और दीर्घकालिक प्रभाव विश्लेषण की व्यवस्था की जा सकती है। एक स्वतंत्र चुनावी व्यय एवं लोकलुभावन नीति मूल्यांकन आयोग गठित किया जा सकता है, जो घोषणापत्रों की व्यवहार्यता पर सार्वजनिक रिपोर्ट जारी करे। साथ ही, राज्य के बजट का एक न्यूनतम प्रतिशत पूंजीगत व्यय हेतु सुरक्षित रखने का संवैधानिक प्रावधान भी किया जा सकता है। साथ ही यह भी आवश्यक है कि पारदर्शिता को बढ़ाया जाए। यदि कोई राज्य मुफ्त बिजली देना

चाहता है, तो उसे यह स्पष्ट करना चाहिए कि उसका वित्तीय स्रोत क्या है, कितनी अर्थी तक योजना चलेगी, और उसका ऋण- जोड़ी भी अनुपात पर क्या प्रभाव पड़ेगा। संसद और विधान सभाओं में पूर्व-अनुमोदन और सार्वजनिक विमर्श की बाध्यता लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व को कठोर करेगी। न्यायालय का हस्तक्षेप नीति-निर्माण में प्रत्यक्ष दखल नहीं बल्कि संवैधानिक मर्यादा की तत्परता से याद दिलाना है।

साथियों बात अगर हम इस मुद्दे पर एक सख्त कानून बनाए जाने की करें तो मेरा सुझाव है कि भारत में चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा रेवड़ियाँ (मुफ्त उपहार, नकद लाभ, वादों के रूप में प्रत्यक्ष प्रलोभन) बॉटने का मुद्दा अक्सर लोकतांत्रिक नैतिकता और वित्तीय अनुशासन से जोड़ा जाता है। इस संदर्भ में यदि अत्यंत सख्त और निवारक कानून की परिकल्पना की जाए, तो वे प्रभावशाली, स्पष्ट और दंडात्मक भावना वाले होने चाहिए। मेरे विचार से संभावित कठोर विधेयक/अधिनियम नाम सुझाए जा रहे हैं: (1) लोकतांत्रिक श्रुति एवं चुनावी प्रलोभन निषेध अधिनियम, 2026 (2) चुनावी रेवड़ी उन्मूलन एवं कठोर दंड अधिनियम, 2026 (3) राजकोषीय अनुशासन एवं लोकलुभावन वादा नियंत्रण अधिनियम, 2026 (4) चुनाव प्रलोभन अपराध नियंत्रण एवं दंड संहिता अधिनियम, 2026 (5) राजनीतिक वित्तीय पारदर्शिता एवं मुफ्त वितरण प्रतिबंध अधिनियम, 2026 (6) जनमत प्रलोभन निषेध एवं लोकधन संरक्षण अधिनियम, 2026 (7) चुनावी लोकलुभावन घोषणापत्र विनियमन एवं दंड अधिनियम, 2026 (8) लोकतंत्र संरक्षण (अवैध चुनावी लाभ वितरण निषेध) अधिनियम, 2026 (9) राजनीतिक जवाबदेही एवं अनुदान दुरुपयोग निवारण अधिनियम, 2026 (10) चुनावी भ्रष्ट आचरण (मुफ्त वस्तु/नकद प्रलोभन) पूर्ण प्रतिबंध

अधिनियम, 2026 साथियों बात अगर हम इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में समझने की करें तो भी यह प्रश्न नया नहीं है। कई लोकतांत्रिक देशों में चुनावी वादों की सीमा तय करने के लिए राजकोषीय नियम बनाए गए हैं। यूरोपीय संघ में सदस्य देशों पर घाटे और ऋण की सीमा संबंधी मानक लागू हैं। लैटिन अमेरिकी देशों ने अतीत में लोकलुभावन व्यय के कारण आर्थिक संकट झेले हैं, जहाँ अत्यधिक सस्मिडी और मुफ्त वितरण ने मुद्रास्फीति और मुद्रा अवमूल्यन को जन्म दिया। भारत जैसे उभरते अर्थतंत्र के लिए यह चेतावनी है कि अल्पकालिक राजनीतिक लाभ दीर्घकालिक आर्थिक अस्थिरता का कारण न बन जाए।

अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि प्रश्न यह नहीं कि कल्याणकारी राज्य होना चाहिए या नहीं, भारत का संविधान स्वयं एक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना करता है। प्रश्न यह है कि क्या कल्याण दीर्घकालिक सशक्तिकरण की दिशा में है या अल्पकालिक निर्भरता की ओर? क्या संसाधनों का उपयोग उत्पादक परिणामों में हो रहा है या उपभोग में? क्या करदाताओं के धन का उपयोग पारदर्शी और न्यायसंगत है? और क्या भविष्य की पीढ़ियों पर ऋण का बोझ अनावश्यक रूप से डाला जा रहा है? न्यायापालिका की हालिया टिप्पणियाँ इस बहस को एक नई गंभीरता प्रदान करती हैं। यदि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका मिलकर एक संतुलित ढांचा विकसित करें जहाँ सामाजिक न्याय, आर्थिक अनुशासन और लोकतांत्रिक नैतिकता का समन्वय हो तो भारत न केवल अपनी राजकोषीय स्थिति को सुरक्षित रख सकेगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर एक उत्तरदायी लोकतंत्र का उदाहरण भी प्रस्तुत करेगा। रेवड़ी संस्कृति पर नियंत्रण केवल कानून का विषय नहीं, बल्कि राजनीतिक इच्छाशक्ति, नागरिक जागरूकता और आर्थिक विवेक का सम्मिलित परिणाम होगा। यही संतुलन भारत को सशक्त, आत्मनिर्भर और दीर्घकालिक विकास की दिशा में अग्रसर कर सकता है।

## राज्यसभा द्विवार्षिक चुनाव 2026 के वर्षपर्यंत सियासी मायने

कमलेश पांडेय

चिरंजीवी सदन 'राज्यसभा' के द्विवार्षिक चुनाव के लिए वर्ष 2026 में विभिन्न चरणों में खाली होने वाली कुल 71-75 सीटों के लिए चुनाव होगा जो पूरे वर्ष अप्रैल और नवंबर में भरी जाएंगी। लिहाजा, इन चुनावों के राजनीतिक मायने गहन व अहम हैं, क्योंकि ये चुनाव जहाँ एनडीए की बहुमत मजबूती बढ़ा सकते हैं, वहीं विपक्ष को भी कमजोर कर सकते हैं। इससे भाजपा व उसके साथियों का चुनावी हौसला बढ़ेगा।

जहाँ तक इनकी प्रमुख तारीखों की बात है तो चुनाव आयोग ने पहले चरण में 10 राज्यों की 37 सीटों पर चुनाव घोषित किए हैं। जिसके लिए अधिसूचना 26 फरवरी को जारी होगी, नामांकन 5 मार्च तक, और मतदान-मनगणना 16 मार्च 2026 को। जबकि बाकी सीटें नवंबर में भरी जाएंगी, जिसमें उत्तर प्रदेश की 10 सीटें सबसे महत्वपूर्ण हैं। इन दस चुनावी राज्यों में से 6 राज्यों में एनडीए की सरकार है, जबकि 4 राज्यों में इंडी गठबंधन के घटक दल सरकार में हैं। जहाँ तक राज्यवार सीटों की बात है कि पहले चरण में महाराष्ट्र की 7, तमिलनाडु की 6, पश्चिम बंगाल की 5, बिहार की 5, ओडिशा की 4, असम की 3, हरियाणा की 2 और छत्तीसगढ़ की 1 सीटें शामिल हैं, जबकि दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 10 और झारखंड, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना आदि की 20 से अधिक सीटों के लिए नवंबर में चुनाव होगा।

जहाँ तक उच्च सदन राज्यसभा में वर्तमान दलगत स्थिति की बात है तो राज्यसभा में कुल 245 सीटें हैं, जहाँ भाजपा के 103 और एनडीए के 121-129 सांसद हैं। जबकि विपक्षी इंडिया (INDIA) ब्लॉक के पास 78-80 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस के 27 सांसद हैं। जहाँ तक इन चुनावों के राजनीतिक प्रभाव की बात है तो इन चुनावों में एनडीए की 7-9 या इससे अधिक सीटों का लाभ मिलने का अनुमान

है, जिससे उनकी संख्या 145 तक पहुंच सकती है जबकि विपक्ष को 5 सीटें खोने का खतरा, खासकर बिहार, महाराष्ट्र में है। इससे भाजपा को राज्यसभा में अब कोई भी विधेयक पास करना आसान होगा और सुपरमेजॉरिटी की ओर बढ़त भी उसे मिलेगी।

सवाल है कि इन चुनावों में एनडीए को कितनी सीटें मिलने की संभावना है तो राजनीतिक विश्लेषकों को अनुमान है कि एनडीए को 2026 के राज्यसभा चुनावों में कुल 48 या इससे अधिक सीटें मिलने की संभावना है, जिससे उनकी ताकत 129 से बढ़कर 140+ हो सकती है। पहले चरण के 37 सीटों पर 5-7 का लाभ अनुमानित है, जबकि उत्तर प्रदेश जैसे बाद के चरणों से भी उसे अतिरिक्त मजबूती मिलेगी। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, 71-75 खाली सीटों में से एनडीए को नेट 7-9 या 48 सीटें हासिल हो सकती हैं। चूंकि वर्तमान में एनडीए के 121-129 सदस्य हैं, इसलिए चुनाव बाद 145 तक पहुंचने की उम्मीद है। वहीं बाद के जून-नवंबर वाले दूसरे चरणों के प्रभाव की बात है तो वे भी स्पष्ट हैं। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों में भाजपा को 7-8 मिलनी संभावित है, जबकि ओडिशा, तेलंगाना आदि में स्थिरता मिलेगी। कुल मिलाकर सुपरमेजॉरिटी (123+) पक्की होगी। जबकि विपक्ष को 5 नुकसान होगा।

जहाँ तक इन चुनावों में इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें मिलने की बात है तो इंडिया गठबंधन को 2026 के राज्यसभा चुनावों में कुल 71-75 सीटों में से नेट 5 का नुकसान हो सकता है, जिससे उनकी संख्या 80 से घटकर 75 रह जाएगी। पहले चरण के 37 सीटों पर भी नुकसान की स्थिति बनी हुई है, हालांकि कुंवर राज्यों में स्थिरता संभव है। विश्लेषकों के अनुसार, इंडिया ब्लॉक वर्तमान 80 सीटों से 75 पर सिमट सकता है। कांग्रेस को विशेष रूप से 8 सीटें खोने का खतरा, जिसमें मल्लिकार्जुन खरगे, दिग्विजय सिंह की सीटें भी शामिल हैं। वहीं



बाद के चरणों का प्रभाव भी उसपर पड़ेगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश की 10 सीटों में से सपा को 2-3 मिलनी संभावित है, लेकिन कुल नुकसान होगा। जबकि कर्नाटक, झारखंड में 1-1 सीटों का नुकसान संभव है। ओवरऑल, एनडीए के लाभ से इंडिया कमजोर होगा।

जहाँ तक राज्यवार स्थिति की बात है तो बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए चुनाव होगा। अभी आरजेडी के 2, जेडीयू के 2 और एक सांसद राष्ट्रीय लोक मोर्चा का है। बिहार में 243 सदस्यीय विधानसभा में एक सीट पर जीत के लिए 41 विधायकों के समर्थन की जरूरत है। एनडीए के पास 202 विधायक हैं और एनडीए के खाली 4 सीटें सुनिश्चित हैं, जबकि 5 के लिए जोर आजमाइश बढ़ेगी। क्योंकि यहाँ 35 सीटों के साथ I.N.D.I.A. एक भी सीट अपने बल पर जीतने की स्थिति में नहीं है, ऐसे में 5 विधायकों वाले AIMIM की भूमिका अहम हो जाती है।

यदि पूरा विपक्ष एकजुट होता है तो बिहार में विपक्ष के पास कुल 41 विधायक हो जाते हैं और विपक्ष एक सीट निकाल सकते हैं। ऐसे में यह चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व और विपक्षी एकता की के लिए अगिपरीक्षा होगा।

वहीं महाराष्ट्र विधानसभा में भाजपा के नेतृत्व में सत्तारूढ़ महायुक्ति आसानी से 6 सीटों पर जीत हासिल कर लेगा, वहीं 7वीं सीट के लिए वोटिंग हो सकती है। इसलिए

महाराष्ट्र की राजनीतिक के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार का संसदीय सफर थम सकता है। जबकि हरियाणा से बीजेपी के दो सदस्य विधायक चौधरी और रामचंद्र जांगरा का कार्यकाल 9 अप्रैल को खत्म हो रहा है। इसी प्रकार ओडिशा की 4 सीटों पर चुनाव होगा, जहाँ अभी 2 सीटें बीजेपी और 2 बीजेडी के पास हैं लेकिन विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखें तो बीजेपी की सीटों में इजाफा होना तय है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ में दोनों सीटें अभी कांग्रेस के पास हैं और यहाँ भी बीजेपी जीत दर्ज करने की स्थिति में है।

रही बात तेलंगाना की तो वहाँ से कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी रिटायर हो रहे हैं और बीआरएस के एक कैडिडेट का कार्यकाल पूरा हो रहा है। तेलंगाना में कांग्रेस दोनों सीटें जीत सकती है और हिमाचल में भी कांग्रेस एक सीट जीत सकती है। असम से तीन पश्चिम बंगाल से 5 और तमिलनाडु से भी 6 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होगा। चूंकि इन तीनों राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले इन राज्यों में सत्तारूढ़ पार्टियों के पास राज्यसभा में 3 आसन हैं।

यही वजह है कि क्रॉस वोटिंग से निपटने के चुनौती विपक्ष के सामने रहेगी। क्योंकि राज्यसभा चुनाव में राजनीतिक पार्टियों के लिए अपने अपने विधायकों को

एकजुट रखने की चुनौती हमेशा होती है। पिछले कुछ राज्यसभा चुनावों को देखें तो हरियाणा में कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का सामना करना पड़ा था। इसलिए आने वाले राज्यसभा चुनावों को देखें तो चाहे हरियाणा हो, बिहार हो, यहाँ पर कांग्रेस और सहयोगी दलों को फूक-फूक करकदम रखना होगा। हालांकि कुछ सीटों पर तो रिजल्ट पहले से ही तय है, लेकिन अगर विपक्ष क्रॉस वोटिंग को रोक पाता है तो उसके हाथ भी कुछ सीटें आ सकती हैं। चूंकि राज्यसभा में बीजेपी और एनडीए का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है, इसलिए इस वर्ष 75 सीटों पर होने वाले चुनावों में विपक्ष यदि कारगर रणनीति नहीं बनाता है तो फिर इंडिया गठबंधन वाले कांग्रेस और उसके सहयोगियों की संख्या और घट सकती है, इतना तय है।

जहाँ तक इन चुनावों में प्रमुख नेताओं के प्रभावित होने की बात है तो कई दिग्गजों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है जिसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) के शरद पवार, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, जेयू पी नेता हरिवंश, भाजपा के केंद्रीय मंत्री हरदीप पुर (6 मंत्री सहित) शामिल हैं। वहीं बीएसपी राज्यसभा से साफ हो सकती है क्योंकि उत्तर प्रदेश में भाजपा को 7, सपा को 2 सीटें मिलने की संभावना है। वहीं रामज (RJD) और बीजद (BJD) समेत कई दलों की सीटें घटेगी।

**वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक**

## वर्ग संघर्ष समकालीन परिदृश्य

विदेक रंजन श्रीवास्तव

वर्ग संघर्ष मानव इतिहास की मूल शक्तियों में से एक है जिसने समाजों की संरचना बदली और विश्वव्यापी क्रांतियों का सूत्रपात किया। यूरोप में सामंतवाद से पूंजीवाद का संक्रमण, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के बाद मजदूर आंदोलन, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, 1917 की रूसी क्रांति तथा चीन, वयूवा और लैटिन अमेरिकी आंदोलनों में उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण व प्रशासनिक के शोषण के विरुद्ध संघर्षों ने राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संरचनाओं को उलट दिया। वर्ग विरोध की इसी वैश्विक पृष्ठभूमि में भारत का वर्ग संघर्ष केवल पूंजी और श्रम तक सीमित नहीं, बल्कि वर्ग व्यवस्था, जातीय वर्चस्व, भूमि संबंधों और राजनीति तथा सत्ता की जटिल गठित से जुड़ा है।

भारत में वर्ग संघर्ष वर्ण जाति, औपनिवेशिक शोषण, औद्योगिक पूंजीवाद और वैश्विक पूंजी की बहुस्तरीय प्रक्रिया है जो आज भी सक्रिय है। प्राचीन मध्यकालीन समाज में वर्ग व्यवस्था ने श्रम विभाजन व आर्थिक पदानुक्रम को वैध बनाया। कृषि श्रम व्यवस्था में जमींदार, सामंत व उच्च वर्गीय किसान वर्ग का प्रभुत्व रहा, जबकि भूमिहीन श्रमिक, निम्न जातियों व वीरत समुदायों का कोई अधिकार न था। विद्रोहों की अंतर्धारा में वर्गीय प्रसन्नता व संसाधन कब्जे का आक्रोश जलकता था।

ब्रिटिश औपनिवेशवाद ने जमींदारी व राज्यस्व व्यवस्था तोड़ी, रेयतों, किसानों व जमींदारों में तनाव पैदा किया तथा श्रमण, रेयतों व खदानों से मजदूर वर्ग का निर्माण हुआ। कर संग्रह, कच्चा माल व सस्ता श्रम शोषण से किसान व आदिवासी विद्रोह अक्टू 19वीं सदी के अंत में अंग्रेजों के मजदूर वर्ग ने कारखाना मालिकों व औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध संघर्ष किया। प्रथम विश्व युद्ध, रूसी क्रांति व आर्थिक संकट ने वर्ग चेतना जगाई, अखिल भारतीय ठेके युवक कांग्रेस का निर्माण हुआ। स्वाधीनता आंदोलन में राष्ट्रीय नेतृत्व की राजनीतिक मुक्ति प्राथमिकता के साथ मजदूर किसान संगठनों ने भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन व समानता मांगी। आदिवासी, किसान व मजदूर हड़तालों ने वर्गीय असंतोष दिखाया। स्वतंत्रता के बाद संविधान ने समाजवादी पथ अपनाया, पर भूमि स्वामित्व, उच्च जातीय व पूंजीपति वर्ग का वर्चस्व कायम रहा। आधे श्रमक भूमि सुधार व नकसत आंदोलन ने अग्रगण्य भूमि वितरण व जातीय अग्रणी उजागर किया। शहरों में मजदूर अधिकार भिंते, पर सत्ता अक्षर पूंजी के पक्ष में रहा।

भारत में वर्ग संघर्ष वर्ण जाति से जुटा हुआ है। डॉ. अंबेडकर व मार्क्स के संवाद में कहा गया कि वर्ण संघर्ष के बिना वर्ग संघर्ष अशुभ है। सवर्ण वर्चस्व ने दलित, पिछड़े, आदिवासी व श्रम संरक्षकों की श्रेणीता बनाए रखी। उदाहरण के तौर पर अग्रगण्य मजदूर, लघु किसान व अनुबंध श्रमिक असुरक्षित हुए। वर्ग संघर्ष खेत खदानों, सॉर्टिंग सेक्टर व युग्मियों तक फैला रहा। यहाँ वर्ग, आर्थिक स्थिति के साथ सांस्कृतिक पूंजी, जातीय पहचान व राजनीतिक पहलू निर्धारित करता है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में सवर्ण विरोधी नारे वर्ण व वर्ग तनावों का संक्षेप हैं। बहुजन समाज पार्टी के उदयकाल में प्रतिनिधित्व राजनीति थी। दिवंगत प्रयाग सिंह के समर्थक मंडल विरोधी आंदोलन आरक्षण के विरुद्ध गद्यम वर्गीय आक्रोश था। आज पूंजी सी नीतियों के विरुद्ध प्रतिरोध निजीकरण व बाजारीकरण से जुड़ा हुआ है जो वीरतों को प्रभावित करता है। मंडल आंदोलन अग्रसर की साझेदारी के विरुद्ध था जबकि वर्तमान स्वर संरचनात्मक प्रसन्नताओं पर हैं। सवर्ण विरोधी भाषा संरचना विरोध से ट्रेड की ओर मुड़ सकती है। यह वंशजातक है क्योंकि युवा श्रम की दिशा तय करेगा। विधायिकात्मक अग्रगण्यता पोषित करें, पर वह विवेकपूर्ण हो, वर्ग धृवीकरण लोकतंत्र को प्रभावित करता है। अंततः वर्ग संघर्ष का मूल प्रश्न, संसाधनों व सत्ता पर नियंत्रण है। अतः वर्ग संघर्ष स्वरूप बदल कर फिर फिर प्रकट होता रहता है। तार्किक, सम वितरण, नैसर्गिक न्याय ही वर्ग संघर्ष का किंवदंत समाधान है।

## विदेशी नागरिकता, विदेशी जुड़ाव और लोकतांत्रिक जवाबदेही

गजेन्द्र सिंह

**लोक नीति विश्लेषक**

हाल के दिनों में आसाम से कांग्रेस सांसद गौरव गोरोई के विदेशी एलिजाबेथ कोलबर्न की पत्नी नागरिकता और उनके पेशेवर संबंधों को लेकर चर्चा हुई है। इसी के साथ यह सवाल भी उठा है कि उनके दोनों बच्चों की नागरिकता को लेकर कोई स्पष्ट और सार्वजनिक जानकारी अब तक क्यों सामने नहीं आई है। यह बहस किसी व्यक्ति के निजी जीवन में झांकने के लिए नहीं बल्कि सार्वजनिक पद पर बैठे लोगों से जुड़ी पारदर्शिता और राष्ट्रीय हित जैसे बड़े सवालों से जुड़ी है।

लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा केवल कानूनी अनुपालन तक सीमित नहीं होती। उनसे यह भी अपेक्षित होता है कि वे सार्वजनिक विश्वास के उच्चतम मानकों पर खरे उतरें, विशेषकर तब, जब बात नागरिकता, विदेशी पेशेवर संबंधों, दोहरी

निष्ठाओं या संभावित हित-संघर्ष की हो— इन विषयों पर अस्पष्टता स्वयं में संदेह को जन्म देती है। इसलिए ऐसी जानकारियों का स्पष्ट, सत्यापित और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होना लोकतांत्रिक जवाबदेही का एक अनिवार्य तत्व माना जाता है।

यह प्रश्न भारत में नया नहीं है। पिछले दो दशकों में अनेक वरिष्ठ राजनेताओं, संवैधानिक पदाधिकारियों और शीर्ष नौकरशाहों के पारिवारिक सदस्यों— विशेषकर बच्चों—का विदेश में अध्ययन, निवास या पेशेवर करियर सार्वजनिक रूप से रिपोर्ट होता रहा है। उदाहरणस्वरूप, पूर्व रिजर्व बैंक गवर्नर रघुमन राजन ने स्वयं स्वीकार किया कि उनका पेशेवर और पारिवारिक जीवन लंबे समय तक अमेरिका में केंद्रित रहा। इसी प्रकार विदेशी मंत्री एस. जयशंकर के पुत्र ध्रुव जयशंकर ने जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त की और अमेरिका में कार्य विन्यास से जुड़े रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित



डोभाल के पुत्र विवेक डोभाल के ब्रिटिश नागरिक होने और इंग्लैंड में रहने की रिपोर्ट्स सामने आई हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के पुत्र ध्रुव गोयल ने हार्वर्ड से पढ़ाई कर न्यूयॉर्क में एक वेंचर फंड स्थापित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की पुत्री वांगमयी परकाला ने अमेरिका की नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त की। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी की पुत्री लीतामया ने यूनिवर्सिटी ऑफ वारिक से पढ़ाई की और अमेरिका में बसने की जानकारी सार्वजनिक डोमेन में रही है। इसी तरह, राजद नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी का अपने बच्चों को विदेश में बसने की सलाह वाला बयान सार्वजनिक विवाद का विषय बना। भाजपा नेता संजय धोत्रे के पुत्र नकुल धोत्रे ने कैलिफ़ोर्निया से

और पेशेवर गतिविधियों भी यूके और अमेरिका से जुड़ी रही हैं। ये उदाहरण दर्शाते हैं कि वैश्विक शिक्षा और करियर आज भारतीय सार्वजनिक जीवन की एक स्थापित वास्तविकता बन चुके हैं।

प्रशासनिक तंत्र में भी ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहाँ कैबिनेट सचिव स्तर के अधिकारियों, संवैधानिक संस्थाओं से जुड़े नौकरशाहों और नीति-निर्माताओं के बच्चे पश्चिम में बस बेसिक मिलिटरी ट्रेनिंग शुरू की। प्रियंका गांधी वाड़ा के दोनों बच्चों—रायहान और मिराया—ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा ग्रहण की। अंतरराष्ट्रीय शर शर शिक्षा जुड़वाँ पुत्र ईशान और कनिष्क थरुकर का पालन-पोषण और करियर विदेशों में रहा है तथा सलमान खुशीद के बच्चों की शिक्षा

जुड़ाव, नागरिकता स्थिति और वैश्विक हितों की पारदर्शी घोषणा का कोई स्पष्ट और समान मानक होना चाहिए?

यहाँ से चीन की तथाकथित “नेकेड लीडरशिप पॉलिसी” की चर्चा प्रसंगिक हो जाती है। यह नीति उन अधिकारियों पर लागू होती है जिनके पति/पत्नी या बच्चे विदेश में रहते हैं, विदेशी नागरिकता रखते हैं या स्थायी निवास के धारक हैं। चीनी कम्प्यूटिस्ट पार्टी का तर्क रहा है कि ऐसे अधिकारी विदेशी प्रभाव, ब्लैकमेल, हितों के टकराव और राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिमों के प्रति अपेक्षाकृत अधिक संवेदनशील हो सकते हैं। इसी सोच के तहत 2010 के बाद चीन ने ऐसे अधिकारियों को संवेदनशील पदों से हटाए, पदोन्नति रोकने, अतिरिक्त निगरानी लागू करने और कई मामलों में अनिवार्य स्थानांतरण जैसे कदम उठाए। भ्रष्टाचार-विरोधी अभियानों में इस नीति का उपयोग एक संदेश के रूप में किया गया—कि राज्य

सत्ता और निजी जीवन के वैश्विक हितों का टकराव स्वीकार्य नहीं है। निस्संदेह, चीन का मॉडल लोकतांत्रिक नहीं है और भारत जैसे संवैधानिक लोकतंत्र में उसकी नकल संभव भी नहीं। लेकिन इसका मूल सिद्धांत—नेतृत्व में पारदर्शिता, संस्थागत निष्ठा और बाहरी प्रभाव से दूरी—आज वैश्विक विमर्श का हिस्सा बन चुका है।

अतः प्रश्न यह नहीं है कि भारत को चीन जैसी नीति अपनानी चाहिए या नहीं। असली प्रश्न यह है कि एक लोकतांत्रिक गणराज्य में, जहाँ सत्ता जनता के विश्वास पर टिकी है, संवेदनशील सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों से पारिवारिक और वैश्विक हितों को लेकर कितनी पारदर्शिता अपेक्षित है? यह बहस व्यक्तियों को कटघरे में खड़ा करने के लिए नहीं बल्कि राष्ट्रीय हित, संस्थागत ईमानदारी और लोकतांत्रिक जवाबदेही के मानकों को स्पष्ट करने के लिए आवश्यक है।

# कांग्रेस ने पूर्व मंत्री एवं उनके पत्नी की गिरफ्तारी पर पुलिस की आलोचना की, अविलम्ब रिहा करने की मांग की

कार्तिक कुमार परिष्ठा, स्टेट हेड - झारखंड

रांची, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो ने कांग्रेस कमेटी के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनकी पत्नी, पूर्व विधायक निर्मला देवी की गिरफ्तारी का विरोध किया। उन्होंने कहा कि दोनों शांतिपूर्ण धरना पर बैठे थे और ग्रामीणों के हक-अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। कांग्रेस ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताते हुए तत्काल रिहाई की मांग की है। केशव महतो ने कहा कि योगेंद्र साव और निर्मला देवी एन टी पी सी द्वारा अधिग्रहित जमीन के उचित मुआवजे को लेकर आंदोलन कर रहे थे। प्रभावित ग्रामीणों से बातचीत का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जमीन अधिग्रहण से पहले लोग सामान्य जीवन जी रहे

थे, लेकिन अधिग्रहण के बाद कई परिवार अब तक मुआवजे से वंचित हैं। उन्होंने बताया कि हजारों बाग के प्रशासनिक अधिकारियों से इस संबंध में बातचीत की गई है और दोनों नेताओं की रिहाई की मांग रखी गई है। साथ ही राज्य सरकार के रवैये पर सवाल उठाते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि हेमंत सरकार में अधिकारी कानून का पालन नहीं कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि 19 फरवरी को दोपहर करीब तीन बजे पुलिस ने योगेंद्र साव और निर्मला देवी को हिरासत में लिया। योगेंद्र साव पर बड़कागांव, केरेडारी और पगार ओपी समेत कई स्थानों में मामले दर्ज हैं। वे 31 दिसंबर 2025 से चंडी बरियातू कोल माईंस परियोजना को लेकर धरने पर बैठे थे और पुलिस ने उन्हें धरना स्थल से ही गिरफ्तार किया।



# ताज, मंत्रालय देने व छीनने वाली मां पाउडी आज भी प्रासंगिक है झारखंड की राजनीति में

चर्चा का विषय बना है दो मंत्री एक सांसद द्वारा पाउडी उपासक पूर्व विधायक के पूजन स्थल पर स्कूल बना डालना

कार्तिक कुमार परिष्ठा, स्तंभकार झारखंड

प्राचीन सिंहभूम जिसका एक शहर भगवान कृष्ण के उन सोलह कला यानी सरायकेला, उसका संबंध पुराण काल से उत्कल से रहा है। स्कन्द पुराण के विष्णु खंड के 26 वें एवं 27 वें श्लोक में स्वर्णरेखा तथा ऋषिकुल्या नदी बीच की भूमि को ओडू देश कहा गया है। ये ओडू शब्द ओडिया वीरों के संदर्भ में प्रचलित रहा है जो पुराना नाम रहा ओडिशा का। जहां दारुब्रह्म (लकड़ी देहधारी) देवता के रूप में जगन्नाथ विराजमान हैं। आप पुरी धाम में भैरव होते और भैरवी दुर्गा रूपी विमला आज भी पूजा जाती हैं वहीं। मां विमला एवं जगन्नाथ हर ओडिया देशी रियासतों की देवी देवमाने जाते हैं, जहां उनकी पर्याय नाम कहीं पाउडी तो कहीं कटक चंडी, कहीं समलेश्वरी आदि विर्णित है। आज की दे का बाद आज 24 देशी राज्य ओडिशा तथा 2 झारखंड स्थित है। ये झारखंड में अब सरायकेला व खरसावां है, कालांतर में राजनीतिक कारण वश नहीं रखे गये पर आज नौबत जब ओडिया को मिटाने की जारी है वैसे में इलाके की अधिष्ठात्री देवी को ही लोगों ने चुनाव में उतार दिया है। पालिका, पंचायत चुनाव प्रचार कुछ ऐसा लगने लगा है सरायकेला में। यहां सिंहभूम की इष्टदेवी मां पाउडी देवी



ही अब देखा जाय तो चुनाव लड़ रही है। मूल वासियों में राजा सरायकेला का चुनाव प्रचार कुछ इस देवी से आधिवादि प्राप्त कर लड़ने की बात प्रचार वाहन में तेज आवाज में गुंज रही है, जहां लोग कायल हैं इस पर। आखिर कौन है यह देवी, रहती सरायकेला में कहां। सरकार बनने बिगाड़ने में अधिप्राय क्या रही है। बड़ा ही रोचक प्रसंग है। रूठ गयी तो कुर्सी तक छीने जाने के चर्चे राजनीति पटल में आज भी अट्टे पड़े हैं। जय मां पाउडी, जय जगन्नाथ, गजपति राजा का नाम लेते ही सरायकेला वासी अपनी मौलिकता, अपनापन, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को लेकर खींचे चले आ रहे हैं। मानो आज भी वे अपने अन्दर वही अनुभव

राजनीतिक माहौल स्थम्भभूत है। झारखंड के एक पूर्व विधायक अनंत राम टूडू का मां पाउडी के बड़े भक्त हैं। उनके पाउडी स्थल पर सरकार के एक बड़े मंत्री की नजर गड गयी। तब दो मंत्री एवं एक सांसद ने मिलकर आव देखा न ताव उक्त पाउडी जमीन जहां पूर्व विधायक अनंत राम टूडू के पिता मां पाउडी को पूजते थे, वास्तव में वह वीर शासक जगन्नाथ भूईयों का पाउडी स्थल जमीन रहा। वही पर एकलव्य विधालय को जबरन स्थापित करवा दिया मंत्रियों ने। पूर्व विधायक अनंत राम टूडू ने उपायुक्त सरायकेला से लेकर कोर्ट की दरवाजा खटखटाया पर नतीजा ढाक के तीन पात निकाला। जब चुनाव आया तो संबंधित केंद्रीय मंत्री चुनाव हार गये, एक समुदाय ने उनकी बड़ी बेइज्जती कराई। सरायकेला के विधायक मंत्री पद गावां बैठे। उनको लेकर पार्टी में दरार पड़ने लगी थी। अंततः दुसरे पार्टी में जा घुसे पर वहां भी अब कद्र नहीं मिलना चर्चा का विषय बना हुआ है। (रही बात सांसद महोदया की उनकी सीट भी नहीं बची। लोग इन्हें अब मां पाउडी की अभिशाप मान रहे हैं, जहां राजनीति में हर किसी के लिए कद-काठी आज भी तय किया करती है मां पाउडी, राजमहल में वह सरायकेला, सिंहभूम की इष्ट देवी है। संभवतः यही वजह है कि आज चुनाव में मां पाउडी सुखियों में है सरायकेला में साथ ही उनके अनन्य भक्त राजा साहब सरायकेला प्रताप आदित्य।

# 14 मार्च 2026 को आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत - अमरदीप सिंह बैस

अमृतसर, 19 फरवरी (साहिल बेरी)

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अमृतसर द्वारा 14 मार्च 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में आज सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अमृतसर श्री अमरदीप सिंह बैस की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य अधिकतम योग्य मामलों के निपटारे हेतु प्रभावी समन्वय एवं सहयोग सुनिश्चित करना था। श्री बैस ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन Punjab State Legal Services Authority के कार्यकारी अध्यक्ष एवं Punjab and

Haryana High Court के माननीय न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा के कुशल मार्गदर्शन एवं गतिशील नेतृत्व में किया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि सत्र प्राग अमृतसर के प्रशासनिक न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति रोहित कपूर द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अमृतसर को लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु निरंतर मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अमृतसर श्रीमती जतिंदर कौर के समर्पित प्रयासों एवं सतर्क पर्यवेक्षण से राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को और अधिक मजबूती मिली है। श्री बैस ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से मामलों का निपटारा त्वरित, सरल एवं निष्पक्ष तरीके से किया जाता है। आपसी



सहमति के आधार पर दिए गए निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होते हैं, जिससे पक्षकारों को लंबी कानूनी प्रक्रियाओं से राहत मिलती है। लोक अदालत के आयोजन से न्यायालयों में लंबित मामलों का बोझ भी कम होता है तथा आपसी सौहार्दपूर्ण समाधान का वातावरण विकसित होता है।

उन्होंने बताया कि समझौता योग्य आपराधिक मामले, यातायात चालान, बैंक वसूली प्रकरण, बिजली बिल संबंधी मामले, पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण आदि मामलों का आसानी से निपटारा किया जा सकता है। आम जनता से अपील की गई है कि वे अपने लंबित मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रस्तुत कर इसका पूर्ण लाभ उठाएं। बैठक के दौरान बैंकों एवं बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया तथा आपसी सहमति के माध्यम से अधिकतम मामलों का निपटारा कर लंबित मामलों की संख्या कम करने और वादियों को त्वरित न्याय उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

## शीर्षक - माँ कहती है

बच्चों पढ़ो तुम मन लगाकर, माँ कहती है हमें ये अक्सर, तुम हो साहसी ताकतवर, भगाओ परीक्षाओं का डर।

परीक्षाएं जीवन का हिस्सा, मत बनाओ भय का किस्सा, तुम्हारी मेहनत का ये शीशा, दिखाती है तुम्हें सही दिशा।

नहीं कदम उठाना नुकसानदेह, जहाँ हो कोई भी प्रश्न या संदेह, गुरुजनों से पूछो तुम निडर स्नेह, तुम श्रानंदर से भरपूर निःसंदेह।

ईमानदारी से करो तुम पढ़ाई, अध्ययन में हो रूचि गहराई, नित्य मेहनत ने तकदीर बनाई, शिक्षा ने ही किस्मत चमकाई।

त्याग दो परीक्षाओं का डर, मत दो तन-मन को ये जहर, भय को मत दो हवा भीतर, तुम पर करता सब निर्भर।

आपके स्नेह और प्यार का धन्यवाद रचना स्वरचित और सर्वाधिकार सुरक्षित

## आर्थिक विकास आकलन...

भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी है अर्थव्यवस्था, धरलू खपत, सुधारों व तेज आर्थिक वृद्धि अवस्था। भविष्य में देश 'तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था' का दर्जा, यह मुकाम हासिल होगा इसमें नहीं कोई भी हर्जा।

आर्थिक विकास के आंकड़ों से जुड़े हुए आकलन, पैमाने में 'महंगाई' को स्थिर करें पहले के संकलन। एक तरफ विकास की चमकती हुई तस्वीर है पेश, दूसरी तरफ महंगाई की स्थिति बयां नया परिवेश।

इस वर्ष के शुरुआत में ही महंगाई में हुई बढ़ोतरी, खाद्य सामग्री एवं जरूरी वस्तुओं के दाम चढ़ोतरी। महंगाई का सबसे ज्यादा असर गरीब व मध्य वर्ग, भोजन, ईंधन व स्वास्थ्य का सरकार समझ लें दावे। (संदर्भ-आर्थिक विकास के दावे तेज।)

संजय एम तराणकर (कवि, लेखक व समीक्षक) इन्दौर-452011 (मध्य प्रदेश)



## गिरफ्तारी के दौरान नियमों का पालन न करने पर हाई कोर्ट नाराज: गिरफ्तार आरोपी को जमानत मिली, DSP ने माफ़ी मांगी

मनोरंजन शासमल, स्टेट हेड ओडिशा

कटक: हाई कोर्ट ने उस घटना पर नाराजगी जताई है जिसमें एक पुलिस अधिकारी ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय कानून के नियमों का पालन नहीं किया। हाई कोर्ट ने नाजिम मलिक को जमानत दे दी है, जिसे मलकानगिरी जिले के पोडिया पुलिस स्टेशन में गैर-कानूनी मारिजुआना तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। हाई कोर्ट ने मलकानगिरी स्वतंत्र कोर्ट को आवेदक को 1-1 लाख रुपये के दो जमानत के बदले जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है। जस्टिस गौरीशंकर सतपथी की बेंच ने नाजिम को रंगुलर जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया।

दूसरी ओर, मामले के जांच अधिकारी और पोडिया पुलिस स्टेशन के तत्कालीन DSP रामेश्वर प्रधान वरुंअली पेश हुए और बयान देकर माफ़ी मांगी। उन्होंने अपने लिखित बयान में गाली-गलौज और अश्लील भाषा के इस्तेमाल के लिए माफ़ी मांगी थी। उनका ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने का कोई

इरादा नहीं था। हलफनाम में कहा गया है कि वह भविष्य में सावधान रहेंगे। हाई कोर्ट ने एफिडेविट स्वीकार कर लिया और उस भविष्य में सावधान रहने और ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने की चेतावनी दी। हाई कोर्ट ने कहा कि कानून के नियमों के अनुसार, गिरफ्तार किए गए

# गिरफ्तारी के दौरान नियमों का पालन न करने पर हाई कोर्ट नाराज: गिरफ्तार आरोपी को जमानत मिली, DSP ने माफ़ी मांगी

मनोरंजन शासमल, स्टेट हेड ओडिशा

कटक: हाई कोर्ट ने उस घटना पर नाराजगी जताई है जिसमें एक पुलिस अधिकारी ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय कानून के नियमों का पालन नहीं किया। हाई कोर्ट ने नाजिम मलिक को जमानत दे दी है, जिसे मलकानगिरी जिले के पोडिया पुलिस स्टेशन में गैर-कानूनी मारिजुआना तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। हाई कोर्ट ने मलकानगिरी स्वतंत्र कोर्ट को आवेदक को 1-1 लाख रुपये के दो जमानत के बदले जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है। जस्टिस गौरीशंकर सतपथी की बेंच ने नाजिम को रंगुलर जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया।

दूसरी ओर, मामले के जांच अधिकारी और पोडिया पुलिस स्टेशन के तत्कालीन DSP रामेश्वर प्रधान वरुंअली पेश हुए और बयान देकर माफ़ी मांगी। उन्होंने अपने लिखित बयान में गाली-गलौज और अश्लील भाषा के इस्तेमाल के लिए माफ़ी मांगी थी। उनका ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने का कोई

इरादा नहीं था। हलफनाम में कहा गया है कि वह भविष्य में सावधान रहेंगे। हाई कोर्ट ने एफिडेविट स्वीकार कर लिया और उस भविष्य में सावधान रहने और ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने की चेतावनी दी। हाई कोर्ट ने कहा कि कानून के नियमों के अनुसार, गिरफ्तार किए गए

दूरभाष : 9910234578  
9312170612

## सर्व धर्म मित्र मंडल (रजि.)

(दिल्ली राज्य)

कार्यालय: सी-15 ए, डी.डी.ए. प्लेट्स, शिवाजी एन्क्लेव, रघुवीर नगर, नई दिल्ली - 110 027

Chairman  
Prabhu Dyal  
(Ex. ACP, Delhi Police)

President  
K. K. Chhabra

Vice President  
Pritpal Singh  
Kuldeep Sinath

Gen. Secretary  
S. Manohar Singh

Secretary  
Gouri Shankar  
Ritu Verma  
Kanchan Kashap  
Reji John

Joint Secretary  
Pt Ram Avtar.  
Sachin Verma

Cashier  
Ved Parkash

Legal Advisor  
Rajinder Verma

Press Secretary  
V. K. Chaturvedi  
Vinod Negi

टैपल आफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर अलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत) द्वारा - आयोजित एवम् वैक्यूमी काउन्सेलिंग के सौजन्य से -

**"पूर्णता निःशुल्क, कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं, स्वास्थ्य जाँच शिविर**

आपकी तंदुरुस्ती हमारा ध्येय,

दोस्ताना दृष्टि द्वारा आयोजित पूर्णतः निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर

- \* आँखों की जांच,
- \* रक्तचाप,
- \* मधुमेह जांच,
- \* मोतियाबिंद सर्जरी के साथ-साथ
- \* भारतीय लेंस की सुविधा

इस जांच शिविर में पूरी तरह से निःशुल्क प्रदान की जाएगी।

इस जांच शिविर में निम्नलिखित अनुभवी एवं विशेषज्ञ डॉक्टरों एवम् अन्य की निगरानी में जांच,

1. डॉ मनोज कुमार दुबे,
2. रिशु भारद्वाज, एवं
3. विकास राय

जांच शिविर  
दिनांक: 1 मार्च (रविवार) 2026  
स्थान: गुरुद्वारा सिंह समा, शहीद भगत सिंह कॉलोनी, शिवाजी एन्क्लेव, दिल्ली 110027  
समय: 10:00 AM to 02:00 PM

आप सभी से विनय निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में पधारें तथा अपने सगे-संबंधियों और मित्रों को भी साथ लेकर आएं और इस अवसर का लाभ उठाएं।

शिवोपचारकर्ता: मोतियाबिंद सर्जरी के साथ-साथ भारतीय लेंस की सुविधा के लिए मरीजों को अपने खर्च पर

- \* बालाजी हॉस्पिटल
- \* सामन्य हॉस्पिटल

पहुँचना पड़ेगा, पर सर्जरी और भारतीय लेंस निशुल्क रहेगा।

स्वस्थ रहें, जागरूक रहें।  
आपकी सेहत - हमारी प्राथमिकता।

निवेदक  
पिकी कुड्ड, महासचिव  
केके छाबड़ा उपाध्यक्ष  
सुनीता थार्मा सचिव  
अभिषेक राजपूत सचिव

# मैट्रिक परीक्षा शुरू हो गई है। विभिन्न केंद्रों और बोर्ड कार्यालयों का दौरा कर परीक्षा प्रबंधन की निगरानी आयुक्त-सह-शासन सचिव ने की



मनोरंजन शासमल, स्टेट हेड ओडिशा

भुवनेश्वर: राज्यव्यापी वार्षिक हाईस्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा 2026 शुरू हो गई है। माध्यमिक शिक्षा परिषद (बोर्ड) द्वारा यह परीक्षा 19 फरवरी से 2 मार्च तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा के पहले दिन, स्कूल और जन शिक्षा विभाग के आयुक्त-सह-शासन सचिव डॉ.

एन. तिरुमाला नायक ने भुवनेश्वर में विभिन्न परीक्षा केंद्रों का दौरा किया। उन्होंने कटक स्थित बोर्ड के मुख्य कार्यालय का भी दौरा किया। डॉ. नायक ने सभी परीक्षा प्रबंधन तैयारियों, जैसे कि बैठने की व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, प्रश्न पत्र वितरण व्यवस्था और अन्य सुविधाओं की समीक्षा की। उन्होंने शिक्षकों, केंद्र अधीक्षकों, पर्यवेक्षकों और जिला

अधिकारियों के साथ चर्चा कर समन्वय और परीक्षा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने परीक्षा को शांतिपूर्ण तरीके से संचालित करने पर भी जोर दिया। इसी तरह, विभागीय शासन सचिव ने माध्यमिक शिक्षा परिषद के कर्मांड कंट्रोल रूम का दौरा कर परीक्षा प्रबंधन की समीक्षा की।